bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org

संवत 2080 युगाब्द 5125 कुल पृष्ठ –32 जून प्रथम अंक – 21

कमल ज्योति

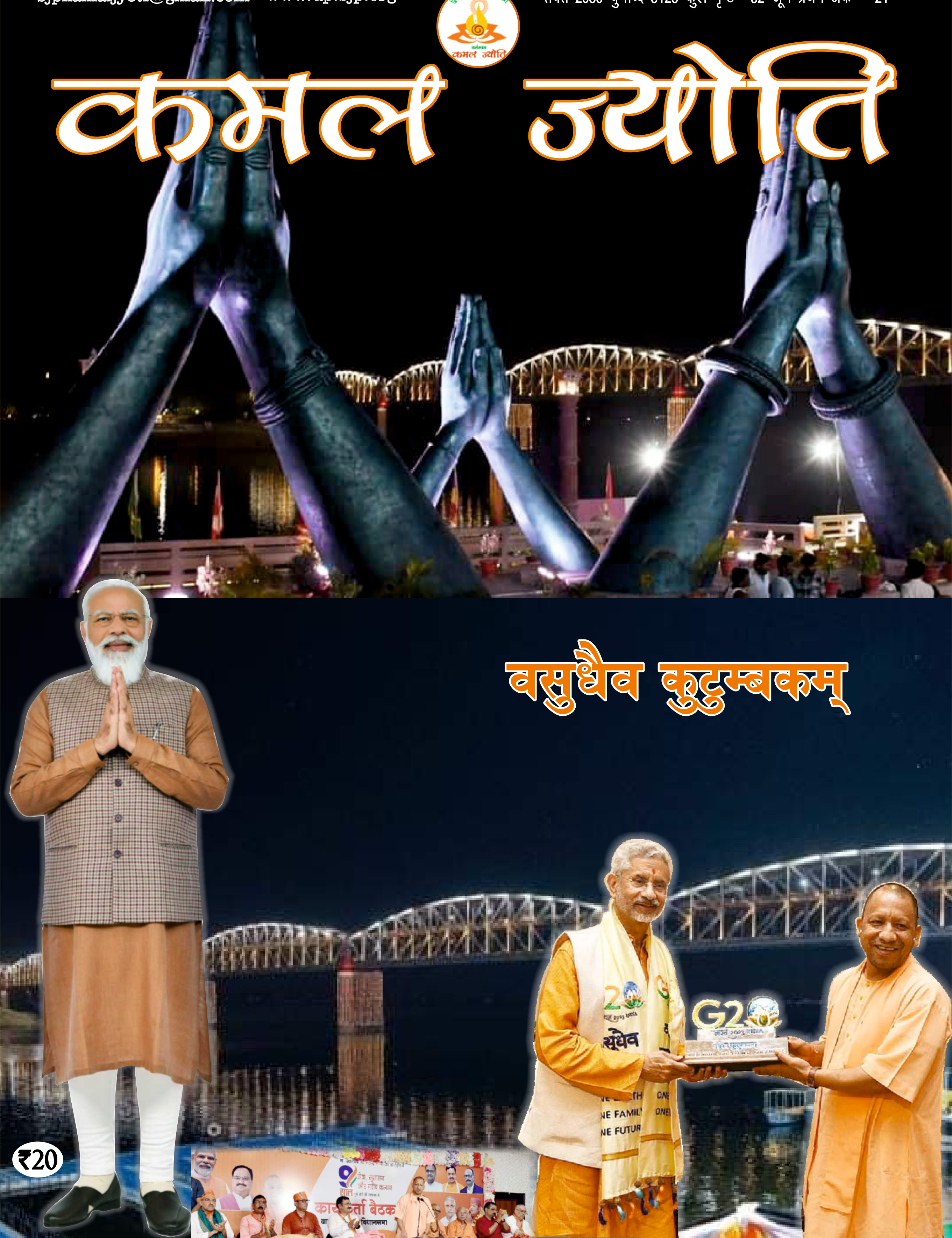

टिफिन बैठक

मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण
साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में

मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में
महासम्पर्क अभियान बैठक

भारतीय जनता पार्टी
काशी क्षेत्र

वर्तमान

कमल ज्योति

संरक्षक

श्री भूपेन्द्र सिंह

सम्पादक

अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध/कार्यकारी सम्पादक

राजकुमार

प्रकाशक

प्रो0 श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक

ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

www.up.bjp.org
bjpkamaljyoti
bjpkamaljyoti
@bjpkamaljyoti

सम्पादकीय

नये भारत का अमृतकाल

भारत का अमृतकाल, श्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 9 साल, भारतीय राजीति में नये भारत के नव निर्माण का कार्यकाल रहा है। राजनीति सेवा का माध्यम बन गयी है। प्रधानमंत्री अब प्रधान सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विकास, सुशासन का दौर है। जल, थल, वायु मार्ग से यात्राएं सुगम हो रही है। गरीब आम आदमी के जीवन में बदलाव दिख रहा है। ऐसे में सरकार की योजनायें जन–जन तक पहुंचे इसके लिए भी जनजागरण की आवश्यकता है। एक भारत–श्रेष्ठ भारत जो इस सरकार में सुदृढ़ होता जा रहा है, जिसमें मोदी जी के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के साथ की अनेक योजनाये प्रभावी हुई हैं जो धरातल पर प्रभावी हो रही है, कथनी–करनी का संकल्प पूरा हो रहा है जैसे गरीब और वंचितों का सम्मान स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.76 करोड़ शौचालय का निर्माण, कोविड के दौरान महिलाओं को 20 करोड़ से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक शहरी और ग्रामीण मकान बने। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 2.88 करोड़ घरों को विद्युतीकरण किया गया। 28 मई 2023 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 8.88 करोड़ नल से जल कनेक्शन, वर्तमान में केंद्र सरकार के 60 प्रतिशत मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से है। इन समुदायों को सशक्त करने के लिए "स्टैंडअप इंडिया योजना" के अंतर्गत 7351 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 48.2 लाख स्ट्रीट वेंडर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत 6,065.72 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसानों का कल्याण किया सुनिश्चित पिछले 9 वर्ष में कृषि बजट पर 5.6 गुना से अधिक की वृद्धि की गई। 2021–26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 93,068 करोड़ की राशि आवंटित की गई। किसानों को मूल्यों के उतार–चढ़ाव से सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में वार्षिक 6000 हस्तांतरित किए जा रहे हैं। लगभग 23 करोड मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चार करोड़ किसानों को 4.7 लाख करोड़ का ऋण जारी किया गया। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक के लाभार्थियों को 1.32 लाख करोड़ वितरित किए गए। नारी शक्ति के लिए नई गति। वेतन सहित मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 3.3 करोड़ से अधिक महिलाओं को 6000 का भुगतान किया गया। भारत में पहली बार 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष का लिंग अनुपात हो गया है। पीएम जन धन योजना के अंतर्गत अब तक महिला लाभार्थियों की कुल संख्या 27.25 करोड़ है। जन औषधि केंद्रों पर 27 फरवरी से अधिक सेनेटरी पैड रू0 1 की दर पर उपलब्ध कराए गए। स्कूलों में लड़कियों के लिए 9.52 लाख अलग शौचालय का निर्माण किया गया। मुद्रा ऋण लाभार्थियों में 27 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई। भारत के अमृत पीढ़ी को सशक्त करना। स्टार्टअप की संख्या में 100 गुना की वृद्धि हुई। वर्ष 2017– 21 में एक स्टार्टअप्स के द्वारा 23 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए। लगभग 4 दशकों के बाद एक क्रांतिकारी नई शिक्षा नीति देश में लाई गई है ,पीएम श्री योजना के तहत 14,500 विद्यालय को अपग्रेड और विकसित किया जाएगा। पिछले 9 वर्षों में 390 नए विश्वविद्यालय 7 नए आईआईएम और आईआईटी की स्थापना की गई। खेलो इंडिया के पूरे देश में खेलों को एक जन अभियान के रूप में परिवर्तित किया और देश में एक नई खेल संस्कृति का विकास किया है। पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उज्जवला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड रसोई घर धूआ रहित हुए। पीएम आवास योजना के तहत कुल लाभार्थियों की 69 प्रतिशत महिलाएं है। पीएम कौशल विकास योजना अंतर्गत 1.37 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया। 7 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 23.24 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए गए। इधर के दिनों में भारत की आर्थिक स्थिति, आम–जन के जीवन स्तर में निरन्तर सुधार नये भारत का उदाहरण बन रहे हैं।

bjpkamaljyoti@gmail.com

'नौ वर्ष' आर्थिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र निर्माण की दिशा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नौ वर्ष की सरकार में देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए साहसिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के आर्थिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र निर्माण के संकल्प में देश के नागरिको की आर्थिक सम्पन्नता समाहित है। महराजगंज के जिला पंचायत सभागार में व्यापारी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि व्यापार व व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भारत के 140 करोड़ लोगों की आत्मनिर्भरता से ही संभव होगा। केन्द्र सरकार की योजनाएं लगातार व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही डबल इंजन की भाजपा सरकार के द्वारा प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था से व्यापारियों के लिए व्यापार के अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अब कोई गुंडा या माफिया किसी व्यापारी से रंगदारी या चौथवसूली नहीं कर सकता है। आज व्यापारी निर्भय होकर स्वाभिमान के साथ अपना व्यापार कर रहे है।

प्रदेश की जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ मोदी सरकार व योगी सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए सभी को सुरक्षा, सभी की सम्पन्नता, सभी को चिकित्सा की प्रतिबद्धता से काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट से उद्योग स्थापित हो रहे है। उन्होंने कहा कि देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ देश को आर्थिक व सामरिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे व्यापारी भाईयों के स्वाभिमान, सम्मान तथा व्यापार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। योगी सरकार ने प्रदेश में गुंडा राज समाप्त करके सुरक्षित वातावरण देने का काम किया है। केन्द्र व प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार व्यापारी कल्याण की योजनाओं तथा नीतियों से व्यापार को सुगम व सरल बनाने के लिए कार्य कर रही है।

लोहिया कला भवन सिद्धार्थनगर में प्रबुद्ध सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि भारत प्रतिभा सम्पन्न राष्ट्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से राष्ट्र की प्रतिभाओं से जुड़कर देश में कई सफल अभियान प्रारम्भ किये। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हुए व्यवस्था परिवर्तन ने नगर, मोहल्लों, गांव, गली, खेत की पगडंडियों तक पहुंचकर राष्ट्र के नायकों का सम्मान देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चित्रकार, गीतकार, संगीतकार, शिल्पकार, लेखक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी सहित आर्थिक, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण तथा सामाजिक, सांस्कृतिक जनजागरण के क्षेत्रों में काम कर रहे प्रबुद्धजन समाज को नई दिशा देने में सक्षम है। भाजपा आप सभी का सम्मान करती है और सदैव आपके श्रेष्ठ कार्यों में आपके साथ है।

विकास योजनाओं में किसी के साथ भाजपा सरकार भेदभाव नहीं करती है। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार विकास योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं करतीं। इस डबल इंजन की सरकार में भारत की संस्कृति का प्रचार–प्रसार हो रहा है। यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है, विश्व में भारत का मान बढ़ाया है।

'रोजगार अभियान' पारदर्शिता व सुशासन का प्रमाण : मोदी

"आज, भारत अपनी राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है, जो आज की दुनिया में बहुत महत्व रखता है; आज भारत सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार के रूप में होती है; आज, सरकार अपने प्रगतिशील आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के लिए जानी जाती है"

"लोगों को बांटने के लिए भाषा का दुरुपयोग किया जा रहा था, सरकार अब भाषा को रोजगार का सशक्त माध्यम बना रही है"

अमृतकाल में भारत निरन्तर विकास की ओर बढ़ रहा रोजगार के साथ सरकारी नौकरियां भी मिल रही हैं। विभिन्न विभागों में 70 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले, एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आजादी का अमृतकाल अभी शुरू ही हुआ है। आपके सामने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी जी–जान से जुट जाना है। मैं आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके परिवारजनों को बहुत–बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं।

बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई हैं, यह अभियान भी अपने–आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे SSC, UPSC और RRB ने पहले के मुकाबले इन व्येवस्थीओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और अभी जो वीडियो दिखाया गया, उसमें उसका जिक्र भी है।

इन संस्थाओं का जोर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल–डेढ़ साल का समय यूं ही लग जाता था, और वो अगर कोई कोर्ट–कचहरी में चला गया तो दो–दो, पांच–पांच साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकलकर अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती हैं।

साथियों,

आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है। भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। आप जानते हैं, एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन टूटना, कितनी–कितनी कठिनाइयां पूरी दुनिया में दिखाई दे रही हैं। इन सबके बावजूद, और मेरे युवा साथियों, इस बात पर आप गौर कीजिए, इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है।

आज विश्व की बड़ी–बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही हैं। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है तो उससे production बढ़ता है, उद्योग का विस्तार होता है, नए–नए उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और स्वाभाविक है बिना नए नौजवानों के ये काम हो ही नहीं सकता, और इसलिए employment बहुत तेजी से बढ़ता है, रोजगार बहुत तेजी

से बढ़ता है।

हमारी सरकार के निर्णयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अवसर पैदा किए हैं, अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विस्तार से वो एक–एक वाक्य में ब्यौरा इसका दे रहे थे। लेकिन मैं जरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है। देश की GDP में इस सेक्टर का योगदान साढ़े छह परसेंट से ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की। utomotive industry ने बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत से Passenger Vehicle का दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। Commercial Vehicle का Export, इतना ही नहीं हमारे Three-Wheeler-Two-Wheelers उनके एक्सपोर्ट में भी बहुत वृद्धि हो रही है। 10 साल पहले ये इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ रुपए के आस–पास थी। आज ये इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ से रनउच लगा करके 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई है। Electric Mobility का भी भारत में लगातार विस्तार हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भारत सरकार की PLI स्कीम से भी बहुत मदद मिल रही है। तेजी से आगे बढ़ते हुए ऐसे ही सेक्टर्स लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बना रहे हैं।

आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी, जनता–जनार्दन के धन का दुरुपयोग, पुरानी जितनी सरकारें आप देखेंगे उनकी पहचान यही बन गई थी। आज भारत को उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। Political stability, ये दुनिया में बहुत मायने रखती है।

आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। एक decisive government- आज भारत सरकार की पहचान उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है। ग्लोबल एजेंसियां लगातार इस बात को घोषित कर रही हैं, अनुमान लगा रही हैं और विश्वास से कह रही हैं कि चाहे हाईवे का निर्माण हो या रेलवे का, Ease of Living की बात हो या फिर Ease of Doing Business की चर्चा, भारत पिछली सरकारों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

बीते वर्षों में भारत ने अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया है। लाखों करोड़ रुपए के इस निवेश ने भी रोजगार के करोड़ों अवसर बनाए हैं। अब जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं एक उदाहरण देता हूं, जो हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। और वो है पानी, और उसके लिए हमने चलाया है जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन, उसके पीछे अब तक करीब–करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।

जब ये मिशन शुरू हुआ था, तो ग्रामीण इलाकों में हर 100 में से यानी 100 घर अगर गांव में हैं, तो सिर्फ 15 घर ही थे, जहां पाइप से पानी आता था। ये मैं एवरेज बता रहा हूं, 100 घर में से 15 घर में पाइप से पानी आता था। आज जल जीवन मिशन की वजह से हर 100 में से बासठ (62) घरों में पाइप से पानी आने लगा है और अभी भी तेज गति से काम चल रहा है। आज देश के 130 जिले ऐसे हैं– ये छोटा क्षेत्र नहीं है, 130 जिले ऐसे हैं, जहां के हर गांव में, हर घर में नल से जल आता है।

जिन घरों में अब साफ पानी पहुंच रहा है, वहां लोगों का समय भी बचा है, लेकिन इससे ज्याइदा महत्वरपूर्ण जो लाभ हो रहा है, और वो गंभीर बीमारियों से भी बचे हैं। पीने का शुद्ध पानी आरोग्य के लिए बहुत बड़ी औषधि बन जाता है। एक स्टडी में सामने आया है कि जब हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगा तो डायरिया से होने वाली 4 लाख मौतें मौत होने से बच गईं, चार लाख जिंदगियां बच गईं, यानी जल जीवन मिशन, चार लाख लोगों का जीवन बचाएगा।

ये स्टडी ये भी कहती है कि हर घर जल पहुंचने से देश के गरीबों के 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बचने वाले हैं, यानी गरीब के घर का पैसा बचने वाला है, मध्यलम वर्ग के परिवार का पैसा बचने वाला है। इन पैसों को उन्हें पानी का इंतजाम करने में, पानी से होने वाली बीमारियों के इलाज में खर्च करना पड़ता था। जल जीवन का एक और बड़ा लाभ ये भी होगा कि इससे महिलाओं का बहुत सारा समय भी बचेगा।

इस रोजगार मेले में नौकरी पाने वाले आप सभी समझ सकते हैं कि सरकार की एक–एक योजना का कितना बड़ा Multiplier Effect होता है। जल–जीवन मिशन का उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है। ऐसे ही आप जब अब सरकारी व्यवस्था में आए हैं तो सरकार की हर योजना को, अपने विभाग के हर लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, ये मेरा आपसे भरोसा भी है, अपेक्षा भी है।

देश में चल रहा ये रोजगार अभियान, पारदर्शिता और सुशासन, गुड गवर्नेंस दोनों का ही प्रमाण है। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई–भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी, तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई–भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थीं। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है।

2014 में हमारी सरकार बनने के बाद, अब भर्ती परीक्षाओं

में पारदर्शिता भी आई है और भाई–भतीजावाद भी खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त होने का लाभ लाखों युवाओं को हुआ है। एक तरफ हमारी सरकार के ये ईमानदार प्रयास हैं तो दूसरी तरफ और ये बात मैं चाहता हूं मेरे नौजवान पूरा समझने का प्रयास करें। हकीकतों के आधार पर कुछ बातें आ रही हैं, दूसरी तरफ भाई–भतीजावाद है।

अभी आपने एक दो दिन पहले मीडिया में आई रिपोर्ट देखी होगी, अखबारों में, टीवी में काफी कुछ देखने को मिला। एक राज्य की उसमें चर्चा है, और चर्चा क्यीा है, एक राज्य में Cash for Job के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं, वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय ले करके आई हैं। उस राज्यल की क्यां पद्धति है, क्यान बात उभर करके आई है, नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाने जाएं तो रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए 'रेट कार्ड' है। रेट कार्ड बताया गया और रेट कार्ड भी कैसा है, छोटे–छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है। अगर आप सफाई कर्मी की नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आपको ये रेट रहेगा, भ्रष्टाचार में इतना देना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो ड्राइवर की नौकरी के लिए ये रेट रहेगा, अगर आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए, टीचर की नौकरी चाहिए, नर्स की नौकरी चाहिए तो आपको ये रेट रहेगा। आप सोचिए हर पद के लिए उस राज्य में 'रेट कार्ड' चला करता है और कट मनी का कारोबार चलता है। देश का नौजवान कहां जाएगा। ये स्वार्थी राजनीतिक दल, Jobs के लिए 'rate card' बनाते हैं।

आप देखिए आपके सामने दो चीजें साथ हैं, एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई–भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टांचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जॉब रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कट मनी। उनका रास्ताा है रेट कार्ड, जबकि हम युवाओं के उज्ज्वो ल भविष्यर को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। रेट कार्ड आपकी काबिलियत को, आपके सामर्थ्य को, आपके सपनों को चूर–चूर कर देते हैं। हम आपके सेफ गार्ड में लगे हैं जो आपके सपनों के लिए जीते हैं। आपके संकल्पोंष को साकार करने के लिए काम करते हैं। आपकी हर इच्छो, आकांक्षा, आपके परिवार की हर इच्छां, आकांक्षा, उसको सेफगार्ड करने में हम लगे हैं। अब देश तय करेगा देश के नौजवानों का भविष्यछ रेटकार्ड के भरोसे चलेगा कि सेफगार्ड व्यसवस्था के अंदर सुरक्षित तरीके से पनपेगा। आज तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में, सरकारी व्यवस्थाओं और सरकारी कर्मचारियों के काम करने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। एक समय था, जब देश के सामान्य नागरिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे। आज सरकार अपनी सेवाएं लेकर, देश के नागरिकों के घर तक पहुंच रही है। अब जनता की अपेक्षाओं को समझते हुए, क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विभिन्न सरकारी दफ्तर और विभाग, जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए काम करने पर जोर, ये हमारी प्राथमिकता है।

इतने सारे मोबाइल एप्स के माध्यम से, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं अब बहुत आसान हो गई हैं। पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। इन बदलावों के बीच, आपको भी देश के नागरिकों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से काम करना है। आपको इन सुधारों को और आगे बढ़ाना है। और इन सबके साथ ही, आप लगातार कुछ न कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति को हमेशा बनाए रखिए।

सरकार में प्रवेश ये जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं हो सकता है। आपको इससे भी आगे बढ़ना है और नई ऊंचाइयों को प्राप्ती करना है। आपके जीवन के नए सपने, नए संकल्पी, नया सामर्थ्यओ उभर करके आना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल, ये ऑनलाइन पोर्टल जो है, IGoT के माध्यम से नई सुविधा बनाई है। हाल ही में, इसके यूजर्स की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई है।

इस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध बवनतेमे का आप पूरा फायदा उठाएं। आपको नौकरी में बहुत काम आएगा। आपको प्रगति करने के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मैं दोस्तोंन आपको यहां से आगे देखना चाहता हूं। आप भी आगे बढ़ें, देश भी आगे बढ़े। ये 25 साल मेरे लिए आपकी प्रगति के भी हैं और हम सबके लिए देश की प्रगति के भी हैं।

अमृतकाल के अगले 25 वर्षों की यात्रा में हम कंधे से कंधा मिलाकर, मिल करके विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज गति से चल पड़ें, आगे बढ़ें। मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवार को बहुत–बहुत बधाई देता हूं।

बहुत–बहुत धन्यवाद।

देश चहमुखी विकास की ओर अग्रसर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के नौ साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में जनसभाएं टिफिन बैठक सम्पर्क संवाद आयोजित की जा रही है। 30 मई से शुरू किए गए महा जनसम्पर्क अभियान में अभी तक सम्पन्न हुए कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों व लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली जनसभाओं की तैयारियों को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने वर्चुअल माध्यम से बैठक किया। वर्चुअल बैठक में महा जनसम्पर्क अभियान के कलस्टर प्रमुख, सांसद, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी सहित अभियान से जुड़े पार्टी पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के नौ वर्षों में देश का चहुंमुखी विकास हुआ और गरीब, वंचित वर्ग मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी जी के रूप में देश को प्रधानसेवक मिला, जिन्होंने पुराने ढर्रे को बदल कर सरकार की योजनाओं को गरीब केन्द्रित किया। जिससे सिस्टम में व्याप्त लीकेज बंद होकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। आज देश की जनता का आशीर्वाद तथा मजबूत समर्थन मोदी जी को लगातार काम करने की शक्ति दे रहा है। भाजपा परम्परागत रूप से अपनी सरकार के काम–काज को विनम्रता से लोक दरबार में लेकर जाती है। इसी परम्परा के अनुसार फिर एक–बार महा जनसम्पर्क अभियान के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाना है। कार्यक्रमों के साथ जनता का जुड़ाव और कार्यकर्ताओं का उत्साह यह बता रहा है कि भाजपा प्रदेश में लक्ष्य 80 अवश्य प्राप्त करेगी।

श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि महा जनसम्पर्क अभियान मिशन 2024 के पूर्व की तैयारी है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में जनसभाओं के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियां लेकर भाजपा जनता के दरबार में पहुंचेगी। वरिष्ठ नेता जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे। चुनाव से पूर्व चुनाव की तैयारी करके भाजपा कार्यकर्ता विजय के लिए उर्वरा भूमि तैयार करना जानते है। जनसभाओं में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता हो इसके लिए हमें योजनापूर्वक कार्य करना होगा।

प्रदेश महामंत्री श्री संजय राय ने कहा कि महासम्पर्क अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में प्रेस कान्फ्रेस, सोशल मीडिया संवाद, प्रबुद्ध सम्मेलन व्यापारी सम्मेलन, वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक, टिफिन बैठक, संयुक्त मोर्चा के सम्मेलनों के बाद अब सार्वजनिक सभाएं भी प्रारम्भ हो चुकी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की 27 जून को श्रावस्ती व केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी

की 29 जून को बिजनौर में जनसभा होगी। लोकसभा क्षेत्रों में हो रही जनसभाओं को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक सहित केन्द्रीय मंत्रिगण व पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्बोधित करेंगे। महासम्पर्क अभियान के अर्न्तगत अभी तक गौतमबुद्ध नगर, फिरोजाबाद, मिश्रिख, गोण्डा में जनसभाएं सम्पन्न हो चुकी है। लखनऊ बहराइच, एटा, खीरी और कैसरगंज सीतापुर, बाराबंकी, श्रावस्ती, प्रतापगढ, हाथरस और देवरिया में हुई।

श्री राय ने बताया कि महासम्पर्क अभियान के अर्न्तगत आयोजित किये जा रहे प्रत्येक कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों को बड़ी संख्या में सहभागिता हो रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने राजधानी लखनऊ के तुलसी गंगा मंडपम, निराला नगर में पूर्वी विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ संवाद एवं 'टिफिन बैठक' में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों के साथ चर्चा की।

जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी महा जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाकर संवाद कर रही है। विपक्षी पार्टी जहां जनता को गुमराह करके आपस में गठबंधन कर रही हैं। जबकि भाजपा का गठबंधन जनता के साथ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्षों में देश का चौमुखी विकास हुआ है और गरीब वंचित वर्ग को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हुई है। पूर्वजों ने जो सपना देखा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के अनुभव के आधार पर पार्टी की कार्य योजना तैयार करें। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी पहली बार सभी नगर निगम में बड़े बहुमत के साथ जीती। पहली बार बड़ी संख्या में नगरपालिकाओ में भी भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। यह सब पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के संकल्पो को पूरा किया है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य शिक्षा सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। धारा 370, राम मंदिर का निर्माण सहित पार्टी कार्यकर्ताओं के सपने साकार हो रहे है।

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व की प्रदेश भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। अपराध के खिलाफ सरकार की नीतियों की चर्चा पूरी दुनिया में है।

हमारा संकल्प है भारत तथा भारतीय संस्कृति के आधार पर पूरी दुनिया में अपनी व्यवस्था स्थापित करें। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद और समर्थन देती है। आज भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी व सर्व स्पर्शी है। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 41 प्रतिशत वोट भाजपा को मिला था, 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी गठबंधन एक होने के बाद भी भाजपा को 51 प्रतिशत वोट हासिल हुए। उन्होंने कहा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जो एजेंडा तय किया सरकार लगातार उसी पर चल रही है। आप सब के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है इसमें कोई भी कार्यकर्ता कभी भी ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में परिवार के लोगों का ही विकास होता है। राष्ट्रीय विचारधारा के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में भी है।

भारतीय संस्कृति में प्रकृति भी, प्रगति भी : नरेन्द्र मोदी

''मिशन लाइफ का मूल सिद्धांत, दुनिया को बदलने के लिए आपकी प्रकृति में बदलाव लाना है''
''जलवायु परिवर्तन के प्रति यह चेतना केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, इस पहल के प्रति वैश्विक समर्थन भी बढ़ रहा है''

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व मानवता को सम्बोधित करते हुए कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को, देश और दुनिया को बहुत–बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम– सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है। और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है, उस पर भारत पिछले 4–5 साल से लगातार काम कर रहा है। 2018 में ही भारत ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्ति के लिए दो स्तर पर काम शुरु कर दिया था। हमने एक तरफ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया और दूसरी तरफ Plastic Waste Processing को अनिवार्य किया गया। इस वजह से भारत में करीब 30 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग की रीसाइकिल कंपलसरी हुई है। ये भारत में पैदा होने वाले कुल सालाना प्लास्टिक वेस्ट का 75 परसेंट है। और आज इसके दायरे में लगभग 10 हज़ार प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर और ठतंदक व्दमते आ चुके हैं।

आज 21वीं सदी का भारत, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत स्पष्ट रोडमैप लेकर चल रहा है। भारत ने Present Requirements और Future Vision का एक Balance बनाया है। हमने एक तरफ गरीब से गरीब को ज़रूरी मदद दी, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का भरसक प्रयास किया, तो दूसरी तरफ भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को देखते हुए बड़े कदम भी उठाए हैं।

बीते 9 वर्षों के दौरान भारत ने ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर अभूतपूर्व फोकस किया है। सोलर पावर हो, LED बल्बों की ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुँच बने, जिसने देश के लोगों के, हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे भी बचाए हैं और पर्यावरण की भी रक्षा की है। बिजली का बिल निरंतर कम हुआ है। भारत की लीडरशिप को दुनिया ने इस वैश्विक महामारी के दौरान भी देखा है। इसी Global Pandemic के दौरान भारत ने मिशन ग्रीन हाइड्रोजन शुरु किया है। इसी Global Pandemic के दौरान भारत ने मिट्टी और पानी को केमिकल फर्टिलाइज़र से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती नैचुरल फार्मिंग की तरफ बड़े कदम उठाए।

ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन इकॉनॉमी के अभियान को जारी रखते हुए, आज दो और योजनाओं की शुरुआत हुई है। बीते 9 सालों में भारत में वेटलैंड्स की, रामसर साइट्स की संख्या में पहले की तुलना में लगभग 3 गुणा बढ़ोतरी हुई है। आज अमृत धरोहर योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के माध्यम से इन रामसर साइट्स का संरक्षण जनभागीदारी से सुनिश्चित होगा। भविष्य में ये रामसर साइट्स इको–टूरिज्म का सेंटर बनेंगी और हज़ारों लोगों के लिए Green Jobs का माध्यम बनेंगी। दूसरी योजना देश की लंबी कोस्टलाइन और वहां रहने वाली आबादी से जुड़ी है। 'मिष्ठी योजना' के माध्यम से देश का मैंग्रूव इकोसिस्टम रिवाइव भी होगा, सुरक्षित भी रहेगा। इससे देश के 9 राज्यों में मैंग्रूव कवर को restore किया जाएगा। इससे समंदर का स्तर बढ़ने और साइक्लोन जैसी आपदाओं से तटीय इलाकों में जीवन और आजीविका के संकट को कम करने में मदद मिलेगी। World Climate के Protection के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। लंबे समय तक दुनिया के बड़े और आधुनिक देशों में विकास का जो मॉडल बना, वो बहुत विरोधाभासी है। इस विकास मॉडल में पर्यावरण को लेकर बस ये सोच थी

कि पहले हम अपने देश का विकास कर लें, फिर बाद में पर्यावरण की भी चिंता करेंगे। इससे ऐसे देशों ने विकास के लक्ष्य तो हासिल कर लिए, लेकिन पूरे विश्व के पर्यावरण को उनके विकसित होने की कीमत चुकानी पड़ी। आज भी दुनिया के विकासशील और गरीब देश, कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों का नुकसान उठा रहे हैं। दशकों–दशक तक कुछ विकसित देशों के इस रवैये को न कोई टोकने वाला था, न कोई रोकने वाला था, कोई देश नहीं था। मुझे खुशी है कि आज भारत ने ऐसे हर देश के सामने Climate Justice का सवाल उठाया है।

भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के दर्शन में ही प्रकृति भी है और प्रगति भी है। इसी प्रेरणा से आज भारत, इकॉनॉमी पर जितना जोर लगाता है, उतना ही ध्यान इकॉलॉजी पर भी देता है। भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व इंवेस्ट कर रहा है, तो Environment पर भी उतना ही फोकस है। अगर एक तरफ भारत ने 4G और 5G कनेक्टिविटी का विस्तार किया, तो दूसरी तरफ अपने forest cover को भी बढ़ाया है। एक तरफ भारत ने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए तो वहीं भारत में WildLife और WildLife Sanctuaries की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि की। भारत आज एक तरफ जल जीवन मिशन चला रहा है, तो दूसरी तरफ हमने Water Security के लिए 50 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर तैयार किए है। आज एक तरफ भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो वो रीन्यूएबल एनर्जी में टॉप–5 देशों में भी शामिल हुआ है। आज एक तरफ भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, तो वहीं पेट्रोल में 20 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी अभियान चला रहा है। आज एक तरफ भारत Coalition for Disaster Resilient Infrastructure-CDRI जैसे संगठनों का आधार बना है तो वहीं भारत ने International Big Cat Alliance की भी घोषणा की है। ये Big Cats के संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है।

मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन Life यानि Lifestyle for environment आज पूरे विश्व में एक Public Movement, एक जनआंदोलन बनता जा रहा है। मैंने जब पिछले वर्ष गुजरात के केवड़िया– एकता नगर में मिशन लाइफ को लॉन्च किया था, तो लोगों में एक कौतुहल था। आज ये मिशन, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए लाइफस्टाइल में परिवर्तन को लेकर एक नई चेतना का संचार कर रहा है। महीना भर पहले ही मिशन Life को लेकर एक कैंपेन भी शुरु किया गया। मुझे बताया गया है कि 30 दिन से भी कम समय में इसमें करीब–करीब 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। Giving Life to My City, इस भावना के साथ, कहीं रैलियां निकलीं, कहीं क्विज़ कंपीटीशन हुए। लाखों स्कूली बच्चे, उनके शिक्षक, इको–क्लब के माध्यम से इस अभियान से जुड़े। लाखों साथियों ने Reduce, Reuse, Recycle का मंत्र अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाया है। बदले स्वभाव तो विश्व में बदलाव, यही मिशन लाइफ का मूल सिद्धांत है। मिशन लाइफ, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, पूरी मानवता के उज्ज्वल भविष्य के लिए उतना ही जरूरी है।

ये चेतना सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की इस पहल को लेकर समर्थन बढ़ रहा है। पिछले वर्ष पर्यावरण दिवस पर मैंने विश्व समुदाय से एक और आग्रह किया था। आग्रह ये था कि व्यक्तियों और कम्यूनिटी में climate friendly behavioral change लाने के लिए इनोवेटिव समाधान शेयर करें। ऐसे समाधान, जो measurable हों, scalable हों। ये बहुत खुशी की बात है कि दुनिया भर के लगभग 70 देशों के हज़ारों साथियों ने अपने विचार साझा किए। इनमें स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर हैं, अलग–अलग डोमेन से जुड़े एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, NGOs हैं और सामान्य नागरिक भी हैं। इनमें से कुछ विशिष्ट साथियों के आइडियाज़ को थोड़ी देर पहले पुरस्कृत भी किया गया है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत–बहुत बधाई देता हूं।

मिशन Life की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय में पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। Lief के लिए थॉट लीडरशिप का संग्रह भी आज जारी किया गया है। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से ग्रीन ग्रोथ का हमारा प्रण और सशक्त होगा। एक बार फिर सभी को पर्यावरण दिवस की अनेक–अनेक शुभकामनाएँ, हृदय से बहुत–बहुत मंगलकामना।

विकास और राष्ट्रीय आत्म विश्वास के 9 साल

दुनिया के सभी समाज सुख और आनंद के इच्छुक रहते हैं। सुख और दुख बारी बारी से आते जाते हैं। मनुष्य समाज का अंग है। लेकिन अनेक अवसरों पर मनुष्य और समाज के बीच अंतर्विरोध भी दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य प्रकृति का भी अंग है। लेकिन मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतर्विरोध भी होते हैं। यह मनुष्य को दुखी करते हैं। समाज शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए राजव्यवस्था विकसित करते हैं। महाभारत में राजा को काल का कारण बताया गया है। राजव्यवस्था समाज को सुखी बनाने के प्रयत्न करती है। राजा या राजव्यवस्था महत्वपूर्ण है। राजव्यवस्थाएँ आनंदमगन समाज के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। मनुष्य की अनेक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। अनेक अभिलाषाएं होती हैं। ऋग्वेद (9.113.10 व 11) में प्रार्थना है, ''जहां सारी कामनाएं पूरी होती हैं। जहां सुखदाई तृप्तिदायक अन्न हों। हे देव हमें वहां स्थायित्व दें।'' अन्न और कामनाओं की पूर्ति पर्याप्त नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं, ''जहां आनंद मोद, मुद और प्रमोद हैं – यत्र आनंदश्च मोदाश्च्स मुद प्रमोद आसते।'' इस मंत्र में आनंद मुद मोद और प्रमोद एक साथ आए हैं। इसी के आगे सुंदर राजव्यवस्था की इच्छा है। आदर्श राजव्यवस्था के आभाव में राष्ट्र सुखी नहीं होते। श्रेष्ठ राजव्यवस्था आनंददायी होती है। इसी प्रार्थना में आदर्श राजव्यवस्था का उल्लेख करते हैं, ''जहां विवस्वान (सूर्य) का पुत्र राजा है, जहां आनंद का द्वार है, आप वहां स्थायित्व दें।'' यहाँ एक आदर्श राजव्यवस्था की प्रार्थना की गई है। राजा या राजव्यवस्था समाज को आनंदपूर्वक रहने के अवसर उपलब्ध कराती है। भारतीय परंपरा में राजा शासक नहीं सेवक है। प्रजा पुत्र है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार राजप्रमुख हैं। वे स्वयं को प्रधानसेवक कहते हैं। बीते माह उनके कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए हैं। इस अवधि की अनेक उपलब्धियां हैं।

9 साल विकास और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का उल्लेखनीय कालखण्ड रहा है। इस अवधि में देश ने अनेक आश्चर्यजनक उपलब्धियां पाई हैं।

9 साल विकास और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का उल्लेखनीय कालखण्ड रहा है। इस अवधि में देश ने अनेक आश्चर्यजनक उपलब्धियां पाई हैं। सारी दुनिया को हिला देने वाली कोरोना महामारी ने यहाँ अनेक चुनौतियाँ पेश की थीं। तमाम देशों में कोरोना के कारण मौत का तांडव था। मोदी जी ने लॉकडाउन का साहसिक निर्णय लिया। कोरोना से लड़ने में सरकार ने पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा पाई। भारत ने दुनिया के अनेक देशों में वैक्सीन भेजी। देश के भीतर कोरोना से लड़ने की प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की। तमाम सर्वेक्षणों में मोदी जी शक्तिशाली ग्लोबल लीडर बताए गए। पाक प्रायोजित आतंकवाद बहुत लम्बे अरसे से भारत पर आक्रामक रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस आतंकवाद से निर्णायक युद्ध हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के ठिकानों पर लक्षित हमला (सर्जिकल स्ट्राइक) हुआ। पूरे देश ने मोदी जी के इस निर्णय की प्रशंसा की। भारतीय संविधान के अनु० 370 को हटाने का निर्णय आसान नहीं था। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने अनु० 370 के शीर्षक में ही लिख दिया था, ''जम्मू कश्मीर के विषय में अस्थाई उपबंध।'' संविधान निर्माता अपनी तरफ से इसे अस्थाई लिख चुके थे। लेकिन संविधान निर्माण (1949) से लेकर 2019 तक यह स्थाई

हृदयनारायण दीक्षित

अनु० बना रहा। मोदी जी के नेतृत्व में अनु० 370 को हटाने का साहसपूर्ण फैसला लिया गया। इस अनुच्छेद के पक्षकार आश्चर्यचकित थे और राष्ट्रवादी शक्तियां प्रसन्न थीं। यह एक अनूठी पहल थी। देश के लोगों में आत्मविश्वास का नया वातावरण देखा गया।

मोदी जी ने अनेक लोकप्रिय योजनाओं की शुरुआत की। जनधन योजना गरीबों के लिए सहारा बन कर सामने आई। इस योजना में खाते पर गरीबों को चेकबुक, पासबुक दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा है। यह एक अनूठी योजना है। इसी तरह किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि से केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाई। इस योजना में केंद्र सरकार देश के छोटे किसानों को साल में 6000 रुपए की सहायता देती है। इस योजना से छोटे किसानों को पर्याप्त राहत मिली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में शुरू हुई थी। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन था। इस समय इस योजना को शुरू किया गया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन मिला। गरीबों के लिए यह योजना बहुत उपयोगी रही। इसी तरह उज्जवला योजना 2016 में शुरू हुई थी। यह एक असाधारण योजना है। महिलाओं के जीवन में क्रन्तिकारी बदलाव आया। इस योजना के अधीन एक साल में 12 गैस सिलेंडर बांटे जाते हैं। प्रत्येक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जाती है। 1 साल में सब्सिडी के रूप में 2400 रुपए का लाभ मिलता है। आयुष्मान भारत योजना सारी दुनिया में विशिष्ट है। नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर बनाई गई यह योजना गरीबों के लिए सहारा बनी। इस योजना में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। दवाई की लागत व चिकित्सा पर अन्य खर्च सरकार देती है। इस योजना में पात्रों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। आयुष्मान कार्ड धारक गरीब सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना इलाज मुफ्त कराते हैं। इस योजना की प्रशंसा सारी दुनिया ने की है।

मोदी सरकार के 9 वर्ष अनेक योजनाओं से भरे पूरे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना के बीमा धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलती है। वर्ष भर में सिर्फ 436 रुपए देकर इस योजना का लाभ मिलता है। गरीबों और वंचितों के लिए यह योजना बड़ी उपयोगी है। इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में शुरू हुई थी। इसका जोर शोर से प्रचार और स्वागत हुआ था। इसका सालाना प्रीमियम केवल 12 रुपए था। अब 2022 से यह 20 रुपए कर दिया गया है। सालाना 20 रुपए में 2 लाख का सुरक्षा कवर महत्वपूर्ण है। ध्यान देने योग्य है। प्रशंसनीय है। अटल पेंशन योजना भी राष्ट्रीय चर्चा में रहती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई यह योजना वस्तुतः एक पेंशन स्कीम है। इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक निवेश करना होता है। 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रत्येक माह अधिकतम 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि निवेश पर निर्भर करती है। गरीबों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना महत्वपूर्ण है। गरीबों को घर बनाने के लिए ऋण पर सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक 3 लाख से कम कमाने वाला व्यक्ति लाभांवित हो सकता है। गरीबों के लिए यह योजना बहुत उपयोगी है। प्रधानमंत्री ने बीते 9 सालों में लोगों से संवाद बनाने के लिए 'मन की बात' कार्यक्रम चलाया है। यह प्रधानमंत्री और आम जनता के बीच सीधा संवाद है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का स्वाभिमान बढ़ा है। दुनिया भारत को हलके में नहीं ले सकती। रूस – यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे थे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी छात्रों को सुरक्षित लाया गया। दुनिया आश्चर्यचकित थी। भारत प्रसन्न है। सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय स्वाभिमान में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में गतिशीलता और स्थिरता। सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत की तमाम उपलब्धियां। भारतीय योग विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। नया संसद भवन संविधान का दिव्य मंदिर है। लोकतंत्र और संविधान की संस्थाएं मजबूत हुई हैं। राष्ट्रजीवन के सभी क्षेत्रों में आशा और उमंग का वातावरण है। वाकई यह कठिन कार्य था लेकिन मोदी के कारण यह नामुमकिन से मुमकिन हो रहा है।

‘जी-20’ वसुधैव कुटुम्बकम् भाव

एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की संकल्पना से ओत प्रोत भारत जी–20 की अध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। वैश्विक मंगल का भारतीय मार्ग सशक्त, सक्षम, समर्थ और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना वाले भारत के लिए यह जिम्मेदारी अपने प्रति दुनिया के बढ़ते विश्वास के रूप में देख रहा है। भारत के वर्तमान सफलताओं का आकलन, तो भविष्य को लेकर आशा प्रकट की जा रही है। दो सौ से अधिक स्थानों पर जनभागीदारी वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम देश भर में आयोजित हो रहें है। जी –20 का अध्यक्ष बनने से विश्व के अल्पविकसित और विकासशील देश आशा भरी नजरों से भी देख रहे हैं। भारत ऐसे मुद्दों पर सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिनसे संपूर्ण विश्व का सुख–शांति–समृधि सुनिश्चित हो। विश्वभर के देशों को यह जिज्ञासा भी है कि जी–20 की अध्यक्षता कर रहा भारत वैश्विक समस्याओं के समाधान में कैसे अपना नेतृत्व देगा? किस तरह से अपनी परंपरा, संस्कृति, विरासत और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखेगा ? क्या भारत वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को अत्यधिक सकारात्मक और सशक्त रूप से प्रस्तुत कर वैश्विक जिज्ञासा का समुचित समाधान और यहाँ के पर्यटन तथा अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर लाभ ले सकेगा? वैश्विक जिज्ञाषा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में भारत तेजी से उभरा है। विगत वर्षो में भारत के पास कई महत्वपूर्ण मंचों का नेतृत्व करने का अवसर आया है । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और शंघाई सहयोग संगठन के बाद एक दिसंबर 2022 से जी–20 का नेतृत्व करने का ऐतिहासिक अवसर भारत को मिला है। जी–20 की अध्यक्षता दर्शाता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओत प्रोत भारत की साख और धाक दोनों विश्व में बढ़ रही है। जी–20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी और 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता हैं। जी–20 समूह में विश्व की दो–तिहाई जनसंख्या समाहित है। भारत एक तरफ विकसित देशों से घनिष्ट सम्बन्ध रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है। भारत का सदैव प्रयास रहा है कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो। बल्कि वन वर्ड भारत पूरे विश्व को एक समान उद्देश्य के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है ।

जी–20 में भारत का मंत्र है एक पृथ्वी एक परिवार एक विश्व। भारत के यही विचार, संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत के लिए जी–20 समूह के समक्ष अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा के दर्शन करवाने का भी बड़ा अवसर है। जी–20 से जुड़े आयोजन दिल्ली के साथ ही देश विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आयोजित हो रहें है। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी विशेषताएं, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपना सौंदर्य और अपनी विशिष्टता है। भारत के प्रति वैश्विक जिज्ञासा और आकर्षण यहाँ के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लोए भी अवसर लेकर आया है।

भारत का स्वस्थ विष्व विज़न

जी–20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठकों में भारत ‘‘सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुख भागभवेत’’ मंत्र के साथ एक वैश्विक स्वास्थ्य संरचना के प्रति अपने संकल्प विजन को रखा है। जी–20 में नीति–वाक्य भी यही है ‘वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर’ जो ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की अवधारणा से निकला है। कोविड–19 महामारी ने सभी देशों के स्वास्थ्य ढांचे झकझोर दिया है। भारत ने जी–20 की अध्यक्षता के मूल उद्देश्य को ‘उपचार, सद्भाव और आशा’ के रूप में रखकर वैश्वीकरण को और अधिक मानव–केंद्रित करने का विजन रखा है जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता है। भारत वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन ढांचे को मजबूत

डॉ. हरनाम सिंह

करने के साथ ही, आपदा रोधी तौर–तरीकों को समाहित कर रहा है। भविष्य की ऐसी चुनौतियों को देखते हुए फार्मास्युटिकल क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण टीकों, चिकित्सा और निदान तक सबकी समान पहुंच बना रहा है। भारतीय जेनरिक दवाइयों की सम्पूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। वित्त वर्ष 2022 में भारत ने 200 देशों को 24.47 बिलियन डॉलर के फार्मा उत्पादों की आपूर्ति की है। सम्पूर्ण विश्व ने भी जीवन रक्षक टीकों की असमानता को दूर करने में भारत की भूमिका को सराहा है। 'वैक्सीन मैत्री' के द्वारा भारत ने सबसे कठिन समय में 100 से अधिक देशों को कोविड वैक्सीन दी थी। भारत कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों को सस्ती HIV दवाएं और एंटी–टीबी जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। भारत की कोशिश है कि इनके लिए क्लिनिकल टेस्ट, अनुसंधान, विकास सहायता और किफायती चिकित्सा उपायों के लिए एक अनुकूल ढांचा तैयार हो। जी–20 सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से भारत एक ऐसा ईकोसिस्टम बना रहा है जिससे निम्न–मध्यम आय वाले देशों को एक समान स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का मंच मिले। भारत के जी–20 की अध्यक्षता एक 'स्वस्थ विश्व' के स्वस्थ विजन को प्रस्तुत करने का भी मंच प्रदान किया है।

जी २० से वैश्विक मंगल

एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की संकल्पना से नया भारत वैश्विक मंगल का मार्ग प्रस्तुत कर रहा है। नया मार्ग जो सशक्त, सक्षम, समर्थ और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। जी–20 की अध्यक्षता भारत के प्रति दुनिया के विश्वास का प्रतीक भी है। वसुधैव कुटुंबकम् की संकल्पना के साथ जी–20 की अध्यक्ष के रूप में भारत ने वैश्विक सुख–शांति–समृधि के लिए काम करना शुरू भी कर दिया है। भारत के वर्तमान सफलताओं का आकलन, तो भविष्य को लेकर आशा प्रकट की जा रही है। ऐसे में हम देशवासियों की यह जिम्मेदारी है कि हम इन आशाओं अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाएं। जब भारत जी–20 की अध्यक्षता कर रहा है तो यह आयोजन हमारे लिए भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। इसलिए 200 से अधिक स्थानों पर जनभागीदारी वाले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित हो रहें है। केंद्र सरकार सामान्य जन को प्रेरित कर रही है की विश्व मंगल के लिए अपनी भूमिका निर्वहन करें। इस अवसर पर कैसे अंतरराष्ट्रीय विश्व की समस्याओं का समाधान भारत अपने नेतृत्व से देगा और साथ ही किस तरह से अपनी परंपरा, संस्कृति, विरासत और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखेगा इसकी तैयारी भी है।

जी-२० आर्थिक सहयोग का मंच

जी–20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो सभी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को वैश्विक रूप देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी–20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के

गवर्नरों की एक मंच के रूप में हुई थी। वर्ष 2007 और 2009 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद शासन प्रमुख के स्तर तक का दर्जा देते हुए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच नाम दिया गया था। जी–20 ने शुरुआत में बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित किया था। बाद में इसका विस्तार हुआ और इसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार का विरोध भी जुड़ गया है।

जी-२० सदस्य देश :

जी–20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा अतिथि के तौर पर कई अन्य देशों को आमंत्रित किया जाता है। जी–20 में भारत, जर्मनी, जापान, इटली, रूस, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, चीन, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, तुर्की और यूरोपीय संघ शामिल है जो विश्व के प्रमुख सशक्त देश हैं। भारत ने अतिथि देश के रूप में स्पेन, बांग्लादेश, मिश्र, मारीशस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, नाइजीरिया और ओमान को आमंत्रित किया है। जी–20 राष्ट्राध्यक्षों का 18वां शिखर सम्मलेन 09–10 सितम्बर 2023 को नई दिल्ली में होगा । इसमें सम्बन्धित मंत्रिस्तरीय बैठक एवं कार्यसमूहों की बैठकों के दौरान जिन प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई और सहमति बनी उसके प्रति प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति की जायेगी।

श्रेयस्कर भारत का संकेत

जी–20 की अध्यक्षता से अग्रणी राष्ट्रों का नेतृत्व कर भारत विकसित होने की दिशा में अग्रसर है। यहाँ से भारत के सशक्त होने एवं विश्व स्वीकार्यता का मार्ग प्रसस्त हो रहा है। भारत ने विश्व को शांति के मार्ग पर अग्रसर करने के अपने संकल्प को दोहराया है। सम्पूर्ण विश्व को सुखी होने का मार्ग दिखाते हुए भारत स्वयं भी उसपर अग्रसर है। पृथ्वी के सभी प्राणी सुखी हों, यह कामना वह व्यक्ति एवं वह राष्ट्र कर सकता है, जो सारी वसुधा को अपना परिवार समझता है। जो उदार, शांतिप्रिय एवं अहिंसक, अपने पराये की संकीर्ण सीमा को लांघकर प्राणीमात्र के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होता है। यही उदात्त विचारधारा भारतीय संस्कृति और जीवन–पद्धति की विशेषता है। इसी विचारधारा से वसुधैव कुटुबंकम एवं सर्वे भवन्तु सुखीन के उद्घोष हुए हैं। 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का नारा भारत के संस्कारों एवं संस्कृति से विश्व कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करेगा। नये प्रतीक चिन्ह के कमल के पुष्प पर विराजित पृथ्वी एवं कमल की सात पंखुड़ियों के माध्यम से सातों महाद्वीपों की एकजुटता और सौहार्द से समृद्धि एवं प्रगति का संदेश मिल रहा है। भारत की छवि लगातार बदलती जा रही है, भारत को दुनिया की महाशक्तियां भी स्थान देने लगी, उससे मार्गदर्शन लेकर अपनी नीतियों को बल देने लगी है। जी–20 की अध्यक्षता भारत को करने का अवसर एक नये, शुभ एवं श्रेयस्कर भारत का संकेत है।

विष्वगुरु की ओर बढ़ते कदम

विश्व के सबसे मजबूत समूह जी–20 की अध्यक्षता, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति में अग्रणी होने के साथ साथ पिछले एक दशक में भारत विश्व पटल पर सशक्त होकर उभरा है। जी–20 देशों के प्रतिनिधि भारत के विभिन्न प्रदेशों एवं शहरों में भ्रमण कर रहें है तो आश्चर्य चकित भी हो रहें है कि सिर्फ एक दशक में भारत में कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। कितने नए हाईवे बन चुके हैं, कितनी नई रेलवे लाइन बनी कितनी रेलवे लाइन की इलैक्ट्रिफिकेशन हुई। पिछले एक दशक में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में तेजी से काम हुआ और भारतीय अधोसंरचना वैश्विक स्तर को टक्कर देती दिख रही है। भारत की आतंरिक दस प्रमुख उपलब्धियों में धारा 370 को समाप्त करने से लेकर राममंदिर सांस्कृतिक पुनरुद्धार, यू.पी.आई. की ताकत, आयुष्मान मैडीकल कार्ड से स्वास्थ्य क्रांति, वन्दे भारत ट्रेन, कोविड वैक्सीनेशन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण ही भारत की अधोसंरचना का निर्माण हुआ है और देश विश्व की महाशक्तियों का मुकाबला कर रहा है। देश ने साफ–सुथरी शासन–व्यवस्था से दुनिया को प्रभावित किया है। जिससे दुनिया के कई देश बेझिझक कारोबार के अवसर भारत में तलाश रहे हैं। यह देश के लिए गर्व एवं गौरव की बात है। आजादी के अमृतकाल में यह देश के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है, जहां से भारत के सशक्त होने एवं विश्व स्वीकार्यता मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विश्व नेता के रूप में उभर रही स्थितियों के कारण भी एक बड़ा अवसर देश को प्राप्त हो रहा है। समूची दुनिया को सुखी होने का मार्ग दिखाते हुए भारत स्वयं भी उस मार्ग पर अग्रसर है ।

भारत जी-२० नेतृत्व में नयी दिशा एवं दृष्टि

भारत कोरा आर्थिक विकास ही नहीं कर रहा है, बल्कि सांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक विकास भी कर रहा है। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा, वाणिज्य कौशल की पहचान और आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण के लिये नए मार्ग भी तैयार कर रहा है। भारत उन देशों में है जो बहुत तेज गति से इलैक्ट्रिक वाहनों को अपना रहा है और इस दिशा में निवेश कर रहा है। डिजिटल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य एवं कृषि से जुड़े विषयों में भारत ने अनूठी उपलब्धियां हासिल की है।

जम्मू-कश्मीर में दिखा बदलाव और नए अवसर

जम्मू–कश्मीर हमेशा ज्ञान और लुभावनी परिदृश्य का केंद्र रहा है। शांति की इस भूमि को पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार होना पड़ा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी राज्य को सशक्त बनाने वाली विकास योजनाएं लेकर आए है जम्मू–कश्मीर में अब एक नया युग देखने को मिल रहा है। जो विकास, शांति और विकास के लिए खुला है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में तीसरी G–20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई। 2019 में जम्मू–कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद ये पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन रहा, जो 24 मई तक चला। इस बैठक में 29 देशों के कुल 61 प्रतिनिधि शामिल हुए। जी 20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक जम्मू–कश्मीर के लिए बदलाव और नए जन्म का अवसर लेकर आयी। जम्मू–कश्मीर सरकार ने पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है। यहां G–20 आयोजित हो रहा है इसलिए कनेक्टिविटी बढ़ है। प्रतिनिधियों का स्वागत इस बात का प्रमाण है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम न केवल शांति के लिए बल्कि जम्मू–कश्मीर में विकास के लाभों को लाने के लिए प्रभावी रहे हैं । जम्मू–कश्मीर तीन दशकों के बाद, नई फिल्म नीति, आधुनिक बुनियादी ढांचे और व्यापार करने में आसानी ने जम्मू–कश्मीर को फिल्मों की शूटिंग के लिए एक पसंदीदा स्थान बना दिया है। जी 20 आयोजन को श्रीनगर में लाकर ऐसा वातावरण बनाया गया है जिसके परिणाम स्वरूप शहरी परिवर्तन हुआ है, सम्मेलनों के लिए क्षमताओं का विस्तार हुआ है। देशव्यापी जी 20 कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य भी दुनिया में भारत की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवाओं को ब्रांड एंबेसडर के रूप में शामिल करना है।

वाराणसी-काशी जी-२० समिट

उत्तर प्रदेश सरकार ने जी–20 समिट की काशी में हो रही बैठक के पहले इस पुरातन नगरी की तस्वीर को बदलकर रख दिया है। वाराणसी में जी20 की यह बैठक 11 से 13 जून में आयोजित है। वाराणसी सदियों से ज्ञान, चर्चा, वाद–विवाद, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रहा है। भारत की विविध विरासत का सार है काशी। देश के विभिन्न शहरों में जी–20 समूह की होने वाली प्रमुख बैठकों में पांच महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में हो रही है। पहली तीन दिवसीय बैठक 17 से 19 अप्रैल के बीच एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप इसके बाद 13 से 15 जून एवम 16 से 18 अगस्त को मंत्री समूह की बैठक होगी। इसके अलावा 28 एवं 29 अगस्त को सस्टनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने संभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी की बैठक को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। यह बैठक बैठक ऐसे समय हो रही है जब विकास से संबंधित चुनौतियां अपने चरम पर हैं, इनमें आर्थिक मंदी, ऋण संकट, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान, बढ़ती गरीबी और असमानता, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, जीवन यापन का लागत संकट, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, और भू–राजनीतिक संघर्ष शामिल हैं। वाराणसी बैठक में लिए गए निर्णय संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) शिखर सम्मेलन में भी योगदान देंगे जो सितंबर में न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। वाराणसी बैठक में दो मुख्य सत्र हो रहें है , एक "बहुपक्षवादः सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई" और दूसरा "हरित विकासः ए लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) दृष्टिकोण"। इस बैठक में लगभग 200 से

ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहें है। प्रतिनिधियों को विश्व के सर्वाधिक प्राचीन शहरों में से एक वाराणसी की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की झलक प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और भ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित हैं। इसमें कृषि वैज्ञानिक परंपरागत मोटे अनाज के साथ ही दुनिया की बढ़ती आबादी को अन्न मुहैया कराने को लेकर स्थायी खेती पर मंथन कर रहें है।

जी20 के प्रतिनिधि काशी में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भी भाग लेंगे। गंगा आरती देखने के लिए एक क्रूज से भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी मेहमानों से आग्रह किया कि वे अपना सारा समय बैठक कमरों में न बिताएं। उन्हें घूमने और काशी को एहसास करने की सलाह दी है और कहा है कि वाराणसी लोकतंत्र की जननी का सबसे पुराना जीवंत शहर है। काशी के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सदियों से ज्ञान, चर्चा, बहस, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जी–20 देशों के विकास मंत्रियों से विकास के इस मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया है और कहा कि यह मॉडल प्रासंगिक हो सकता है, क्योंकि आप सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडा–2030 को गति देने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास मंत्रियों की बैठक के लिए वाराणसी को चुना है। ताकि दुनिया में काशी की सांस्कृतिक विरासत का संदेश जाए। जी–20 का काशी में आयोजन दुनिया के सामने धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सनातन संस्कृति के विविधि रूपों, समावेशी परंपराओं एवं सांस्कृतिक समृद्धि का गवाह बन रहा है। बीते दशक में काशी ने अपनी संस्कृति एवं परम्पराओं के साथ साथ विकास के नए फलक तय किए। सदियों पुरानी काशी जीवंत एवं प्रवाहमान रही है। वसुधैव कुटुंबकम के इसी भाव को भगवान बुद्ध ने काशी की इसी माटी से पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा का संदेश दिया। काशी में हो रहे जी समूह देशों के प्रतिनिधियों के लिए यह शहर सांस्कतिक विरासत के अद्वितीय अनुभवों को साथ ले जाने का एक माध्यम बनेगा, जो भविष्य में काशी को दुनिया के मानस पटल पर एक नए अनुभवों के साथ स्थापित करने में सहयोगी साबित होगा।

भारत की चुनौतियां

भारत के सामने चुनौतियां भी हैं। रूस–यूक्रेन युद्ध से विश्वभर में ऊर्जा और खाद्य संकट खड़ा हो रहा है। विश्व के कई देशों को मंदी का डर सता रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसी महाशक्तियां भी चिंतित हैं। व्यापार की चुनौतियों के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण का संकट भी काफी बड़ा है। भारत–रूस के बीच में रक्षा और व्यापार संबंधी अत्यंत सशक्त संबंध रहे हैं । इंडानेशिया में जी–20की समिट के समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भेंट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्याओं का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र की भूमिका नगण्य हुई है, उस शून्य को भरने का काम भी जी–20करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है उस पर पूरा विश्व अपनी दृष्टी लगाये हैं। क्योंकि भारत विश्व की ग्रोथ का इंजन बनने की ताकत रखता है। रूस–यूक्रेन युद्ध मसले पर भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ, बल्कि उसने अमेरिका के दबाव में आए बिना रूस से सस्ता तेल खरीदा क्योंकि भारत को अपनी जनता के हित पहले देखने हैं। अमेरिका और उसके मित्र देश रूस पर प्रतिबंधों का खामियाजा भुगत रहे हैं। यह भारत का आत्मविश्वास एवं दृढ़ता ही है जहां से दुनिया को अपनी सोच बदलने एवं विश्व को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने की सोच को बल मिल रहा है।

विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं अंतरिक्ष विज्ञान के साथ–साथ भारतीय दर्शन, संस्कृति, जीवन मूल्य, गौरवशाली परंपराएं और मजबूत होती अर्थव्यवस्था विश्व के आकर्षण का केंद्र है। भारत की जिम्मेदारी है कि विश्व को बेहतर करके दिखाएं और अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा से दुनिया को परिचित कराते हुए अपने उच्च शैक्षिक मापदंडो के साथ सेवा परमोधर्मः की भावना को और मजबूत करें। भारत का दायित्व है कि अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें और इस अवसर को चुनौती के रुप में लेकर दुनिया को नये भारत से परिचित कराएं। आजादी के इस अमृतकाल जी–20 का नेतृत्व हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव बढ़ाने वाली है। समृद्ध ज्ञान परंपरा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत अपने को वैश्विक पटल पर स्थापित करने का एक स्वर्णिम अवसर पाया है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास, भारत के पास चुनौतियों से संबंधित समाधान हैं। भारत डिजिटल तकनीक में भी एक बड़ी शक्ति बनने के साथ विश्व में समक्ष उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश है और अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसा शीघ्र हो इसके लिए नीति–नियंत्ताओं को अपने दायित्व का पालन करते समय सचेत रहना होगा। भारत का कद और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे इसके लिए जनता को भी अपने हिस्से की भूमिका भी निभानी होगी। जी–20 की अध्यक्षता से भारत वैश्विक मंच पर एक सशक्त –समृद्ध आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरेगा।

श्री शिव राज्याभिषेक : 'भारत के स्वराज्य' का उद्घोष

आज का दिन बहुत पावन है। आज से 'हिन्दवी स्वराज्य' की स्थापना का 350वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। विक्रम संवत 1731 में आज ही की तिथि, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को स्वराज्य के प्रणेता एवं महान हिन्दू राजा श्रीशिव छत्रपति के राज्याभिषेक और हिन्दू पद पादशाही की स्थापना से भारतीय इतिहास को नयी दिशा मिली। कहते हैं कि यदि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म न होता और उन्होंने हिन्दवी स्वराज्य की स्थापना न की होती, तब भारत अंधकार की दिशा में बहुत आगे चला जाता। महान विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय समाज का आत्मविश्वास निचले तल पर चला गया। अपने ही देश में फिर कभी हमारा अपना शासन होगा, जो भारतीय मूल्यों से संचालित हो, लोगों ने यह कल्पना करना ही छोड़ दिया। तब शिवाजी महाराज ने कुछ वीर पराक्रमी मित्रों के साथ 'स्वराज्य' की स्थापना का संकल्प लिया और अपने कृतित्व एवं विचारों से जनमानस के भीतर भी आत्मविश्वास जगाया। विषबेल की तरह फैलते मुगल शासन को रोकने और उखाड़ फेंकने का साहस शिवाजी महाराज ने दिखाया। गोविन्द सखाराम सरदेसाई अपने पुस्तक 'द हिस्ट्री ऑफ द मराठाज–शिवाजी एंड हिज टाइम' के वॉल्यूम–1 के पृष्ठ 97–98 पर लिखते हैं कि 'मुस्लिम शासन में घोर अन्धकार व्याप्त था। कोई पूछताछ नहीं, कोई न्याय नहीं। अधिकारी जो मर्जी करते थे। महिलाओं के सम्मान का उल्लंघन, हिंदुओं की हत्याएं और धर्मांतरण, उनके मंदिरों को तोड़ना, गोहत्या और इसी तरह के घृणित अत्याचार उस सरकार के अधीन हो रहे थे। निज़ाम शाह ने जिजाऊ माँ साहेब के पिता, उनके भाइयों और पुत्रों की खुलेआम हत्या कर दी। बजाजी निंबालकर को जबरन इस्लाम कबूल कराया गया। अनगिनत उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं। हिन्दू सम्मानित जीवन नहीं जी सकते थे'। ऐसे दौर में मुगलों के अत्याचारी शासन के विरुद्ध शिवाजी महाराज ने ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो भारत के 'स्व' पर आधारित था। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। धर्म–संस्कृति फिर से पुलकित हो उठी।

हिन्दवी स्वराज्य 350 वर्ष के बाद भी प्रासंगिक है क्योंकि वह जिन आदर्शों पर खड़ा था, वे सार्वभौगिक और कालजयी हैं। हिन्दवी स्वराज्य की चर्चा इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि संयोग से केंद्र में आज ऐसी शासन व्यवस्था है, जो भारत को उसके 'स्व' से परिचित कराने के लिए कृत–संकल्पित है। हिन्दवी स्वराज्य का स्मरण एवं उसका अध्ययन हमें 'स्व' के और अधिक समीप लेकर जाएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरदार के अनुसार, "शिवाजी के राजनीतिक आदर्श ऐसे थे कि हम उन्हें आज भी लगभग बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा को शांति, सार्वभौमिक सहिष्णुता, सभी जातियों और पंथों के लिए समान अवसर, प्रशासन की एक लाभकारी, सक्रिय और शुद्ध प्रणाली, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नौसेना और मातृभूमि की रक्षा के लिए एक प्रशिक्षित सेना देने का लक्ष्य रखा"। यदि हम वर्तमान मोदी सरकार की शासन व्यवस्था के सिद्धाँतों को देखें, तो उसके केंद्र में भी लगभग यही विचार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बार–बार यह उल्लेखित करते हैं कि उनकी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र को लेकर चल रही है। शिवाजी महाराज ने राज्य को 'स्व' का आधार देते हुए भारत केंद्रित नीतियों को बढ़ावा दिया, जैसे– फारसी और अरबी को हटाकर स्वभाषा का प्रचलन, विदेशी मुद्रा की जगह स्वराज्य की नयी मुद्रा शुरू करना, किसानों और सरकार के बीच से बहुत समय से प्रचलित आढ़ती व्यवस्था को हटाकर राजस्व संग्रह करने के लिए रैयतवाडी व्यवस्था प्रारंभ की, सीमा सुरक्षा के नये प्रबंध, विदेश नीति में बदल, राज्य व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अष्टप्रधान मंडल की व्यवस्था, सैन्य सशक्तिकरण पर जोर और मुगलों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके नयी व्यवस्थाएं खड़ी करना। हिन्दवी स्वराज्य की भाँति ही वर्तमान केंद्र सरकार भी मानती है कि कृषि एवं उद्योग को प्रोत्साहन देकर लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। जब लोग आत्मनिर्भर होंगे, तब ही राज्य भी आत्मनिर्भर होकर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। वर्तमान सरकार ने कृषि सुधारों के लिए आगे बढ़कर पहल की है। हालांकि

लोकेन्द्र सिंह

कुछ लोगों की जिद के कारण सरकार को तीन ऐतिहासिक कृषि कानून वापस लेने पड़े। मुद्रा प्रबंधन में भी सरकार शिवाजी महाराज की तरह सजग है। जाली नोटों से निपटने एवं कालेधन पर चोट करने के लिए केंद्र सरकार ने विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। जब एक बार फिर सरकार को लगा कि दो हजार रुपये के नोट के रूप में कालाधन जमा होने लगा है और जाली नोट की संख्या भी बढ़ रही है, तब एक बार फिर सरकार ने मुद्रा प्रबंधन के सिद्धांत का पालन करते हुए इस बड़े नोट के प्रचलन को बंद कर दिया।

कल्याणकारी राज्य की स्थापना का एक और सिद्धांत है कि राजनीति में परिवारवाद के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने 'स्वराज्य' की स्थापना की, तब उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह भोंसले घराने का शासन नहीं है, यह मराठा साम्राज्य भी नहीं है, यह हम सबका 'स्वराज्य' है। इसमें सबकी समान भागीदारी है। यह ईश्वरी की इच्छा से स्थापित 'हिन्दू साम्राज्य' है। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को महाराष्ट्र साम्राज्य, मराठी साम्राज्य, भोंसले साम्राज्य नाम न देकर, उसे 'हिन्दवी साम्राज्य' और 'हिन्दू पद पादशाही' कहा। मुगल साम्राज्य के ज्यादातर किलों का प्रमुख औरंगजेब का कोई रिश्तेदार ही था। जबकि हिन्दवी स्वराज्य में किलेदार की नियुक्ति की कड़ी और पारदर्शी व्यवस्था थी, तय मापदंड पर खरा उतरनेवाले व्यक्ति को ही किले की जिम्मेदारी मिलती थी। उनके राज्य के शासन में किसी के लिए अनुशासन में ढील नहीं थी। जो नियम सामान्य नागरिक के लिए थे, उनका पालन महाराज भी उतनी ही कठोरता से करते थे। अपराध करने पर उनके रिश्तेदार भी सजा और कानून से बच नहीं सकते थे। उनका शासन सही अर्थों में प्रजा का शासन था। मछुआरों से लेकर वेदशास्त्र पंडित, सभी उनके राज्यशासन में सहभागी थे। स्वराज्य में छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं था। पन्हाल गढ़ की घेराबंदी में नकली शिवाजी बनकर महाराज की रक्षा करनेवाले शिवा काशिद, जाति से नाई थे। अफजल खान के समर प्रसंग में शिवाजी के प्राणों की रक्षा करनेवाला जीवा महाला था। आगरा के किले में कैद के दौरान उनकी सेवा करने वाला मदारी मेहतर था।

हिन्दवी स्वराज्य के 350वें वर्ष में जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो एक बात स्पष्ट तौर पर दिखायी देगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र एक व्यक्ति या राजा नहीं, वे एक विचार और एक युगप्रवर्तन के शिल्पकार थे। इसलिए जब ईस्वी सन् 1680 में शिवाजी महाराज ने हिन्दवी स्वराज्य की राजधानी दुर्गदुर्गेश्वर 'रायगढ़' की गोद में अंतिम सांस ली, तो उनका विचार उनके साथ समाप्त नहीं हुआ। अकसर यह होता है कि कोई प्रतापी राजा अपने बाहुबल और सैन्य कौशल से बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वह साम्राज्य ढह जाता है। शिवाजी महाराज के साथ ठीक उलटा हुआ। उनके देवलोकगमन के बाद हिन्दवी साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ और वह समय भी आया जब मुगलिया सल्तनत धूलि में मिल गई तथा भारतवर्ष में हिन्दवी स्वराज्य का परम पवित्र भगवा ध्वज गर्व से लहराने लगा।

छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के समय मुगल साम्राज्य उत्तर में काबुल प्रांत से लेकर दक्षिण में तिरुचिरापल्ली तक, पश्चिम में गुजरात तक और पूर्व में असम के बहुत बाहरी इलाके तक, , भारत के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था। ऐसा कह सकते हैं कि मुगल बादशाह की हुकूमत देश के हर हिस्से में चलती थी। लेकिन 1719 में अत्याचारी औरंगज़ेब की मृत्यु के 12 वर्षों के भीतर ही मराठों ने दिल्ली में प्रवेश किया और मुगल राजधानी के मुख्य मार्गों में भगवा ध्वज लेकर पथ–संचलन साफ संदेश दे दिया कि अब भारत विदेशी आक्रांताओं के चंगुल से स्वतंत्र होकर रहेगा। 1740 तक मालवा और बुंदेलखंड पर मराठों का आधिपत्य हो गया। 1751 में उन्होंने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया और बंगाल और बिहार पर चौथ लगाया। 1757 में उन्होंने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया और 1758 में हम उन्हें पंजाब को अधीन करते हुए और अटक के किले पर भगवा ध्वज लहरा दिया। महादजी सिंधिया ने 1784 में दिल्ली से मुगल सल्तनत को पूरी तरह उखाड़कर फेंक दिया। 1784 से 1803 तक दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर हिन्दू संस्कृति का परम पवित्र 'भगवा ध्वज' गर्व से लहराया। अब भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हिन्दवी स्वराज्य के योद्धाओं के कंधों पर आ गई थी। इसलिए दक्षिण में तटीय क्षेत्रों को पुर्तगालियों के कब्जों से मुक्त कराना हो या फिर उत्तर में अफगानिस्तान के मैदानों से प्रवेश करनेवाले आक्रांताओं के वार झेलने हों, हिन्दू साम्राज्य की सेना ही मोर्चा लिए दिखायी देती है। हमें इस तथ्य से सबको अवगत कराना चाहिए कि अंग्रेजों के हाथों में भारत के शासन के सूत्र मुगलों से नहीं, अपितु हिन्दुओं के पराभव से पहुँचे। सन् 1803 में असई की लड़ाई के साथ ही भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ गया, जो तीसरे आंग्ल–मराठा युद्ध–1818 में अंग्रेजों की जीत के साथ लंबे समय तक स्थायी हो गया। स्मरण रखें कि हिन्दवी स्वराज्य पर हमला करने के लिए मुगलों ने ही अंग्रेजों को आमंत्रित किया था।

हिन्दवी स्वराज्य का यह सामर्थ्य, उसका वैभव, उसके सिद्धांत और आदर्श, आज भी हमारे लिए प्रेरणा और पथ–प्रदर्शक हैं। इसलिए 'स्वराज्य–350' के स्वर्णिम अध्याय के पृष्ठ उलटने के कर्मकांड से ऊपर उठकर उसके आदर्श को धरातल पर उतारने और उसे प्रगाढ़ करने का वातावरण बनाना चाहिए।

पुण्यतिथि विशेष

स्वतंत्रता के ध्वज वाहक : भगवान बिरसा

बिरसा मुंडा

रांची (झारखंड) में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी या अन्य सजा इसलिए न दी कि विद्रोह न भड़क जाये, इसलिए धीमा जहर दिया और 9 जून को सन् 1900 को खून की उल्टियाँ शुरु हो गईं, अंतिम समय में 3 बार उलगुलान! उलगुलान! उलगुलान! शब्द कहते हुए महारथी बिरसा ने पार्थिव शरीर त्याग दिया और उनकी आत्मा परमपिता से जा मिली।

भारतीय इतिहास में स्व के लिए पूर्णाहुति देने वाले महानायकों में बिरसा मुंडा को भगवान् के रुप में शिरोधार्य किया गया है। "न भूतो न भविष्यति"के आलोक में धरती आबा, ईश्वर का अवतार, हिंदुत्व के ध्वजवाहक ,भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान् क्रांतिकारी योद्धा हमारे महा महारथी" बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर शत् शत् नमन है।

विडंबना यह है कि भगवान् बिरसा ने जिन उद्देश्य और संकल्प के लिए अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों से संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया, उसे भलीभाँति समझा ही नहीं गया। यदि समझ लिया गया होता तो भारत से ईसाई मिशनरियों का सूपड़ा साफ हो जाता और जनजातियों का व्यापक रुप से मंतातरण नहीं होता।

इसलिए वर्तमान संदर्भ में भगवान् बिरसा के विचार और संघर्ष का इतिहास जानना परम आवश्यक है, ताकि समस्त हिन्दू समाज देश में हो रहे ईसाई मिशनरियों,लव जेहाद की आड़ में धर्मांतरण, वामियों और तथाकथित सेक्यूलरों के षड्यंत्रों का एकजुट हो सामना कर सके।

शब्द ब्रम्ह होते हैं और जैंसे ही "उलगुलान" "हूल जोहार "भूमि जोहार" और "जय हो जोहार हो, लड़ाई आर–पार हो" शब्द अर्थ देते हैं, तो महा महारथी श्रीयुत बिरसा मुंडा के गौरवशाली इतिहास के पन्ने खुलने लगते हैं।

महा महारथी, महानायक बिरसा मुंडा मुझे हमेशा से महान् क्रांतिकारी योद्धा के साथ ईश्वर का अंशावतार के रुप दिखते हैं।कभी – कभी ऐंसा लगता है कि राणा पूंजा (पूंजा भील) जिसने महाराणा प्रताप के साथ मुगलों के विरुद्ध सर्वस्व अर्पित कर अपने गोरिल्ला युद्ध से छक्के छुड़ा दिये थे, वही बिरसा मुंडा के रूप में अवतरित हुए, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये।

याद आ रहा महारथी बिरसा का वह नारा "अबुआ दिशुम, अबुआ राज" (हमारा देश, हमारा राज्य),ऐंसा लगता है कि लोकमान्य तिलक जी के "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार" और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प,नेताजी सुभाष चंद्र बोस के "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा के संकल्प, तथा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में, बिरसा मुंडा के नारे की सुगंध है।

भुजंग मेश्राम ने क्या खूब लिखा है महारथी बिरसा के लिए कि

"मैं केवल देह नहीं..
मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ....
पुश्तों और उनके दावे मरते नहीं..
मैं भी मर नहीं सकता..
मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता..
उलगुलान! उलगुलान! उलगुलान!
(उलगुलान =जल – जंगल – जमीन पर दावेदारी के लिए –कोलाहल, क्रांति, संघर्ष, आंदोलन)।

झारखंड के उलिहातु गांव में माता करमी हातु और पिता सुगना मुंडा के यहाँ 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का अवतरण हुआ था। बिरसा कुशाग्र बुद्धि के थे इसलिए अंग्रेजों ने जर्मन स्कूल में भर्ती करवाया, वहां उनको बिरसा डेविस नाम दिया गया, परंतु जल्दी ही बिरसा ने

ईसाई मिशनरियों के षडयंत्र को समझ लिया और धर्मांतरण का विरोध किया और ये कहते हुए स्कूल छोड़ दिया कि "साहेब साहेब एक टोपी है"।
ईसाई धर्म स्वीकार करने सभी मुंडाओं को हिन्दू धर्म में पुनःदीक्षित किया। 'साहब–साहब एक टोपी' यानी अंग्रेज सरकार, ईसाई मिशनरी सब एक ही है। इसी बीच बिरसा का आनंद पांडा से संपर्क हुआ। उन्होंने रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। इन ग्रंथों का उनके मन पर काफी गहरा प्रभाव निर्माण हुआ।
धीरे–धीरे एक आध्यात्मिक महापुरुष के रूप में उनका स्थान निर्माण होने लगा। बिरसाइत नाम से उन्होंने एक आध्यात्मिक आंदोलन को प्रारंभ किया। मुंडा दृ उरांव और अन्य कई समाज के हजारों लोग इस आंदोलन में सम्मिलित होने लगे।
भगवान् बिरसा ने उपदेश दिए कि शराब मत पिओ, चोरी मत करो, गौ हत्या मत करो, पवित्र यज्ञोपवीत पहनो, तुलसी का पौधा लगाओ और सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा अर्थात् सूर्य देवता की उपासना करो।यही तो हिंदुत्व के मूल में है। आध्यात्मिक चेतना जागृत होने लगी।
सन् 1894 में छोटा नागपुर में महामारियां फैलीं, तब महारथी बिरसा ने सभी साथियों को अंधविश्वासों से दूर कर अकेले ही सामना किया और विजय हासिल की। बिरसा को देवीय आशीर्वाद मिलने लगा था, इसलिए सभी पीड़ित वर्ग, उनके स्पर्श मात्र से स्वस्थ्य होने लगे थे।
आलोचकों को बता दूँ कि जापान में रेकी पद्धति यही है – आध्यात्मिक स्पर्श। इस समय तक बिरसा भगवान् के अवतार बन गए थे। अंग्रेज़ों ने "इंडियन फॉरेस्ट एक्ट" द्वारा सभी वनवासियों को जंगल से बेदखल कर दिया। यहाँ से आरंभ हुआ महारथी बिरसा का अंग्रेजों के विरुद्ध महान् स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन "उलगुलान"।
महारथी बिरसा ने 1897 से 1900 तक अंग्रेजों से परंपरागत हथियारों से 8 गोरिल्ला युध्द किये अंग्रेजों को भयंकर पराजय दी। सन् 1897 में महारथी बिरसा ने 400 वीर मुंडाओं के साथ" खूंटी थाने "पर भयंकर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। सन् 1898 में" तांगा नदी "के युद्ध में पुनः महारथी बिरसा ने अंग्रेजों की दुर्दशा कर दी। इस समय लाला बाबा के साथ सभी वनवासी, ये गीत गाते कि " कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, रारी कटोंग कटोंग "(काटो बाबा काटो..यूरोपीय साहबों को काटो)।अंग्रेजों में महारथी बिरसा की दहशत व्याप्त हो गई थी। भगवान् बिरसा सभी को एक मुंडारी गीत गाकर अपना संदेश देते –

"विशाल नदी में बाढ़ आई है..
आसमान में धूल भरी आंधी उमड़ – घुमड़ रही है..
ओ! मैना चली जा, चली जादृ
जंगल में आग और धुंआ जोरों से उठ रहा है..
ओ! मैना चली जा,चली जा..
तुम्हारे माँ – बाप बरसाती तूफान में असहाय बहे जा रहे हैं..
ओ! मैना चली जा, चली जा।।"

बिरसा अंग्रेजों के लिए आतंक का पर्याय बन गये थे, परंतु कुटिल और धोखेबाज अंग्रेजों ने हमेशा की तरह हमेशा की तरह कुछ गद्दारों की सहायता से सन् 1900 में दुम्बरी (डोमबाड़ी) की पहाड़ी में घेर लिया तब आमने – सामने की लड़ाई हुई 3घंटे घमासान युद्ध चला लेकिन तोपखाना और बंदूकें भारी पड़ीं।
लगभग 2000 हजार मुंडाओं सहित अन्य जनजातीय समुदाय से बलिदान हुआ। यद्यपि ये युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में रहा परंतु बिरसा सुरक्षित रहे। अंग्रेज़ों ने 500 रुपये का ईनाम रखा इस ईनाम के चक्कर में मुखबिरी हो गयी और 3 फरवरी सन् 1900 को बिरसा पकड़े गए।
जेल जाते समय महारथी बिरसा ने लोगों से आह्वान किया, जो आज भी मुंडारी लोकगीतों में गाया जाता है –

"मैं तुम्हें अपने शब्द दिये जा रहा हूं,
उसे फेंक मत देना,
अपने घर या आंगन में उसे संजोकर रखना।
मेरा कहा कभी नहीं मरेगा।
उलगुलान! उलगुलान! और ये शब्द मिटाए न जा सकेंगे।
ये बढ़ते जाएंगे।
बरसात में बढ़ने वाले घास की तरह बढ़ेंगे।
तुम सब कभी हिम्मत मत हारना।
उलगुलान जारी है।। "

रांची(झारखंड) में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी या अन्य सजा इसलिए न दी कि विद्रोह न भड़क जाये, इसलिए धीमा जहर दिया और 9 जून को सन् 1900 को खून की उल्टियाँ शुरु हो गईं, अंतिम समय में 3 बार उलगुलान! उलगुलान! उलगुलान! शब्द कहते हुए महारथी बिरसा ने पार्थिव शरीर त्याग दिया और उनकी आत्मा परमपिता से जा मिली। महारथी बिरसा का कुल 25 वर्ष का जीवन रहा। 25 वर्ष के अंतराल में उनके द्वारा किए गए विविध पवित्र और पुनीत अनुष्ठान और 4 वर्षों का महासंग्राम अमर रहेगा। महारथी बिरसा का पार्थिव शरीर भी पंच तत्वों में मिलकर अमर हो गया। धिक्कार है, एक दल विशेष के समर्थक और वामी इतिहासकारों पर जिन्होंने महारथी बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम को जल जंगल और जमीन का विद्रोह बताया है और हिन्दू धर्म में वैमनस्यता पैदा करने के लिए प्रकारांतर से कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए है कि हमारा जन्म महा महारथी बिरसा के देश में हुआ।

विजय दिवस 10 जून

पराक्रमी राजासुहेलदेव

कहा जाता है कि इन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच में ग़ज़नवी सेनापति सैयद सालार मसूद ग़ाज़ी को पराजित कर मार डाला था। 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के ऐतिहासिक कल्पित कथा मिरात–ए–मसूदी में उनका उल्लेख है। 20वीं शताब्दी के बाद से, विभिन्न हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने उन्हें एक हिंदू राजा के रूप में चिह्नित किया है जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को हरा दिया।

सालार मसूद और सुहेलदेव की कथा फारसी भाषा के मिरात–ए–मसूदी में पाई जाती है। यह मुगल सम्राट जहाँगीर (1605–1627) के शासनकाल के दौरान अब्द–उर–रहमान चिश्ती ने लिखी थी। पौराणिक कथा के अनुसार, सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा के सबसे बड़े पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के विभिन्न संस्करणों में, उन्हें सकरदेव, सुहीरध्वज, सुहरीदिल, सुहरीदलध्वज, राय सुह्रिद देव, सुसज और सुहारदल समेत विभिन्न नामों से जाना जाता है।

महमूद ग़ज़नवी के भतीजे सैयद सालार मसूद ग़ाज़ी ने 16 वर्ष की आयु में सिंधु नदी को पार कर भारत पर आक्रमण किया और मुल्तान, दिल्ली, मेरठ और अंत में सतरिख पर विजय प्राप्त की। सतरिख में, उन्होंने अपने मुख्यालय की स्थापना की और स्थानीय राजाओं को हराने के लिए सेनाओं को भेज दिया। सैयद सैफ–उद–दीन और मियाँ राजब को बहराइच को भेज दिया गया था। बहराइच के स्थानीय राजा और अन्य पड़ोसी हिंदू राजाओं ने एक संघ का गठन किया लेकिन मसूद के पिता सैयद सालार साहू गाजी के नेतृत्व में सेना ने उन्हें हरा दिया। फिर भी उन्होंने उत्पात मचाना जारी रखा और इसलिए सन् 1033 में मसूद खुद बहराइच में उनकी प्रगति को जाँचने आया। सुहेलदेव के आगमन तक, मसूद ने अपने दुश्मनों को हर बार हराया। अंत में सन् 1034 में सुहेलदेव की सेना ने मसूद की सेना को एक लड़ाई में हराया और मसूद की मौत हो गई।

मसूद को बहराइच में दफनाया गया था और सन् 1035 में वहाँ उसकी याद में एक दरगाह बनाई गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का दावा है कि उस जगह पहले हिंदू संत और ऋषि बलार्क का एक आश्रम था और फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ के द्वारा उसे दरगाह में बदल दिया गया।

आक्रमणकारी सालार मसूद को बहराइच (उत्तर प्रदेश) में उसकी एक लाख बीस हजार सेना सहित जहन्नुम पहुंचाने वाले राजासुहेलदेवपासी का जन्म श्रावस्ती के राजा त्रिलोकचंद के वंशज –मंगलध्वज (मोरध्वज) के घर में माघ कृष्ण 4, विक्रम संवत 1053 (सकट चतुर्थी) को हुआ था। अत्यन्त तेजस्वी होने के कारण इनका नाम सुहेलदेव (चमकदार सितारा) रखा गया।

विक्रम संवत 1078 में इनका विवाह हुआ तथा पिता के देहांत के बाद वसंत पंचमी विक्रम संवत 1084 को ये राजा बने। इनके राज्य में आज के बहराइच,

गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद तथा श्रावस्ती के अधिकांश भाग आते थे। बहराइच में बालार्क (बाल+अर्क = बाल सूर्य) मंदिर था, जिस पर सूर्य की प्रातःकालीन किरणें पड़ती थीं। मंदिर में स्थित तालाब का जल गंधकयुक्त होने के कारण कुष्ठ व चर्म रोग में लाभ करता था। अतः दूर—दूर से लोग उस कुंड में स्नान करने आते थे।

महमूद गजनवी ने भारत में अनेक राज्यों को लूटा तथा सोमनाथ सहित अनेक मंदिरों का विध्वंस किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका बहनोई सालार साहू अपने पुत्र सालार मसूद, सैयद हुसेन गाजी, सैयद हुसेन खातिम, सैयद हुसेन हातिम, सुल्तानुल सलाहीन महमी, बढ़वानिया, सालार, सैफुद्दीन, मीर इजाउद्दीन उर्फ मीर सैयद दौलतशाह, मियां रज्जब उर्फ हठीले, सैयद इब्राहिम बारह हजारी तथा मलिक फैसल जैसे क्रूर साथियों को लेकर भारत आया। बाराबंकी के सतरिख (सप्तऋषि आश्रम) पर कब्जा कर उसने अपनी छावनी बनायी।

यहां से पिता सेना का एक भाग लेकर काशी की ओर चला; पर हिन्दू वीरों ने उसे प्रारम्भ में ही मार गिराया। पुत्र मसूद अनेक क्षेत्रों को रौंदते हुए बहराइच पहुंचा। उसका इरादा बालार्क मंदिर को तोड़ना था; पर राजा सुहेलदेव भी पहले से तैयार थे। उन्होंने निकट के अनेक राजाओं के साथ उससे लोहा लिया।

कुटिला नदी के तट पर हुए राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में हुए इस धर्मयुद्ध में उनका साथ देने वाले राजाओं में प्रमुख थे

रायब,रायसायब, अर्जुन, भग्गन, गंग, मकरन, शंकर, वीरबल, अजयपाल, श्रीपाल, हरकरन, हरपाल, हर, नरहर, भाखमर, रजुन्धारी, नरायन, दल्ला, नरसिंह, कल्यान आदि। वि.संवत 1091 के ज्येष्ठ मास के पहले गुरुवार के बाद पड़ने वाले रविवार (10.6.1034 ई.) को राजा सुहेलदेव ने उस आततायी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब से ही क्षेत्रीय जनता इस दिन चित्तौरा (बहराइच) में विजयोत्सव मनाने लगी। इस विजय के परिणामस्वरूप अगले 200 साल तक मुस्लिम हमलावरों का इस ओर आने का साहस नहीं हुआ। पिता और पुत्र के वध के लगभग 300 साल बाद दिल्ली के शासक फीरोज तुगलक ने बहराइच के बालार्क मंदिर व कुंड को नष्ट कर वहां मजार बना दी। अज्ञानवश हिन्दू लोग उसे सालार मसूद गाजी की दरगाह कहकर विजयोत्सव वाले दिन ही पूजने लगे, जबकि उसका वध स्थल चित्तौरा वहां से पांच कि.मी दूर है।

कालान्तर में इसके साथ कई अंधविश्वास जुड़ गये। वह चमत्कारी तालाब तो नष्ट हो गया था; पर एक छोटे पोखर में ही लोग चर्म रोगों से मुक्ति के लिए डुबकी लगाने लगे। ऐसे ही अंधों को आंख और निःसंतानों को संतान मिलने की बातें होने लगीं। हिन्दुओं की इसी मूर्खता को देखकर तुलसी बाबा ने कहा था —

लही आंख कब आंधरो, बांझ पूत कब जाय
कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाय।।

उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ में राजा सुहेलदेव की वीर वेष में घोड़े पर सवार मनमोहक प्रतिमा स्थापित है।

स्वस्थ भारत : निरोगी काया

आमजन को गुणवत्तापूर्ण व सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हुए केन्द्र की मोदी सरकार स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के संकल्प को साकार कर रही है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की हालत किसी से छिपी नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों की सीएचसी पीएचसी पर चिकित्सक होते थे तो दवा नहीं और दवा होती तो चिकित्सक नहीं। आज यह हालत बदली है। जन स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सरकार निरन्तर काम कर रही है। चिकित्सा शिक्षा के साथकृसाथ अनुसन्धान को समुचित प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत ने गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाओं के उत्पादन व सस्ते इलाज में अपनी पहचान बनाई है। यही कारण है कि आज विश्व के कई देशों के मरीज भारत में अपना इलाज कराने आते हैं।

देश के चिकित्सकों की योग्यता व प्रतिभा के बल पर भारत आज स्वास्थ्य क्षेत्र की हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। योग व आयुर्वेद के क्षेत्र में आज देश और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। मोदी के सद्प्रयासों से विश्व के अनेक देशों में 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा है।

घर बैठे ग्रामीण जनता को चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया गया। चिकित्सा के बुनियादी ढ़ांचे की मजबूती के लिए केन्द्र सरकार ने बजट उपलब्ध कराया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के नौ साले बेमिसाल रहे हैं। इन नौ वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

विगत नौ वर्षों में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। वैसे इन नौ वर्षों में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं लेकिन सरकार की दो योजनाएं गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इनमें पहली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रूपये तक मुफ्त इलाज व जांच की सुविधा प्रदान की जा रही है। अभी तक कैंसर जैसी असाध्य व गंभीर बीमारियों का इलाज गरीब नहीं करवा पाता था। इस योजना के माध्यम से गरीब से गरीब व्यक्ति भी गंभीर बीमारियों का इलाज महंगे से मंहगे अस्पताल में करवा सकता है। इस योजना से सरकारी व निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है। मरीज जहां चाहे वहां पर इस योजना के तहत अपना इलाज करवा सकता है।

आयुष्मान भारत योजना के तहत 10.7 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करते हुए देश के 4.5 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गयी। गुणवत्तायुक्त एवं सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना सरकार ने शुरू की। इसके तहत देशभर में बड़े पैमाने पर जन औषधि मेडिकल स्टोर खोले गये। इन केंद्रों पर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90 फीसदी तक कम कीमत में दवाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में देशभर में 9300 से अधिक जन औषधि केन्द्रों पर सस्ती व ब्रांडेड दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी अब

बृजनन्दन राजू

मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिख रहे हैं।

आज देश में जहां अस्वास्थ्यकर जीवन शैली से उत्पन्न होनेवाले रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं चिकित्सा सेवाएं महंगी होने से गरीब परिवार अपनी जमीन जायदाद बेंचकर भी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते थे। प्रधानमंत्री आयुषमान योजना के कारण आज गरीबों को इलाज मिल रहा है।

घर बैठे ग्रामीण जनता को चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया गया। चिकित्सा के बुनियादी ढ़ांचे की मजबूती के लिए केन्द्र सरकार ने बजट उपलब्ध कराया।

गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए देश में 15 नये एम्स खोले गये। 2014 से पहले देश में मात्र सात एम्स थे। वह भी छह एम्स अटल जी की सरकार में बने। 2014 से पहले भारत में मात्र 387 सरकारी मेडिकल कालेज थे। वहीं वर्तमान में यह संख्या 71 फीसदी तक बढ़कर 700 के करीब हो गई है। पिछले नौ वर्षों में मेडिकल की सीटों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गयी। वर्ष 2014 से पहले देश में एमबीबीएस की सीटें 51 हजार 348 थी वर्तमान में एक लाख 1 हजार 43 सीटें हो गई है। इनमें 52 हजार 778 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज में हैं। वहीं 48 हजार 265 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की पीजी कोर्स की सीटों में 110 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 2014 से पहले ये 31 हजार 185 थी अब यह बढ़कर 65 हजार 335 हो गई है।

प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन भर स्वस्थ एवं सक्षम रहें। कोई भी सरकार या केवल एक पैथी के सहारे सबको स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा और एलोपैथी के साथ–साथ भारत की परम्परागज चिकित्सा पद्धति योग आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना होगा। स्वास्थ्य के संबंध में संपूर्णता से विचार करते हुए केन्द्र सरकार एलोपैथ व आयुष के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। देश के सभी नागरिक निरोग रहें व स्वास्थ्यपूर्ण जीवनशैली अपनाएं इसके लिए जागरूकता के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। समयोचित टीकाकरण होने से मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी आई है। चिकित्सा में विशेषज्ञ परामर्श हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का जहां प्रभावी उपयोग किया जा रहा है वहीं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है।

औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आधुनिक प्रयोगशालाएं बनाई गयी हैं।

पराधीनता के कालखण्डों में भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को भुलाने का काम किया गया। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए आयुष मंत्रालय बनाया गया। नौ वर्षों में योग, आयुर्वेद व होम्योपैथ को प्रोत्साहन दिया गया। मोदी के सद्प्रयासों से पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है।

प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व के कारण ही भारत वैश्विक त्रासदी कोरोना महामारी से उबरने में सफल हो पाया। बहुत ही कम समय में भारत ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के तहत 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन डोज दिए गये। कोविडकाल में भारत ने दुनिया के दो दर्जन से अधिक देशों को मुफ्त में कोरोना का टीका दिया। दुनिया की पहली इंट्रानैसल कोविड–19 वैक्सीन बनाने में भी भारत ने सफलता हासिल की है। वैक्सीन निर्माण और नवाचार क्षमता की दुनियाभर में आज भारत की सराहना हो रही है। मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने में मोदी सरकास फोकस कर रही है। चिकित्सकों के मुताबिक मोटे अनाजों के सेवन से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। स्वाभिमान संपन्न सामर्थ्यशाली स्वस्थ भारत का उदघोष आज चहुंओर हो रहा है।

कैबिनेट ने उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण को दी मंजूरी

किसानों को रियायती, सस्ती और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया तथा सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पीएण्डके उर्वरक प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए खरीफ 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई को रबी मौसम 2022–23 (01.01.2023 से 31.03.2023 तक) के लिए विभिन्न पोषक तत्वों यानी नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों में संशोधन को लेकर उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी और खरीफ मौसम, 2023 (1.4.2023 से 30.09.2023 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए अनुमोदित एनबीएस दरों को मंजूरी दे दी।

एनबीएस योजना द्वारा फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से नियंत्रित है। केंद्र सरकार ने रबी 2022–2023 के लिए 01.01.2023 से 31.03.2023 तक प्रभावी एनबीएस दरों में संशोधन को मंजूरी दी और खरीफ, 2023 (01.04.2023 से 30.09.2023 तक) के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी दे दी, ताकि किसानों को रियायती कीमतों पर फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरक के 25 ग्रेड उपलब्ध हो सकें।

सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पीएण्डके उर्वरक प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए खरीफ 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।

कैबिनेट के फैसले से खरीफ सीजन के दौरान सब्सिडी वाले, किफायती और उचित मूल्य पर किसानों को डीएपी और अन्य पीएण्डके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दोहरा लाभ होगा और पीएण्डके उर्वरकों पर सब्सिडी का युक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।

समय सीमा के पूर्व ही 50 हजार से अधिक अमृत सरोवरों का हुआ निर्माण

अब तक 59,282 उपयोगकर्ता समूह सरोवरों के रखरखाव और उससे अपनी आजीविका सृजन के लिए मिशन अमृत सरोवर से जुड़ चुके हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भविष्य के लिए जल संरक्षण के दृष्टिकोण से 24 अप्रैल, 2022 को मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण और विकास करना है। कुल मिलाकर, इस मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त, 2023 तक 50 हजार अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे निर्धारित समय सीमा के पूर्व प्राप्त कर लिया गया। अब तक 50,071 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 10 मई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में जिला प्रशासन, पंचायतराज पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों, विभिन्न संस्थानों के समन्वित प्रयासों और आमजनों की भागीदारी से 10 मई, 2023 तक अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए लगभग 1,05,243 स्थलों की पहचान की गई, जिनमें से 72,297 स्थलों पर काम शुरु किया गया। अब तक 50,071 हजार अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है।

मिशन अमृत सरोवर का ध्येय यह भी है कि सरोवरों का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार इस तरह किया जाय कि वे स्थानीय सामुदायिक गतिविधियों का केन्द्र बन जाए। सरोवरों के रखरखाव में समुदाय का स्वामित्व हो, ताकि उनका दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस हेतु प्रत्येक सरोवर के लिए उपयोगकर्ता समूह का गठन किया जा रहा है। अब तक 59,282 उपयोगकर्ता समूह सरोवरों के रखरखाव और उससे अपनी आजीविका सृजन के लिए मिशन अमृत सरोवर से जुड़ चुके हैं।

अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा

मुंबई में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय परिषद् में 28 दिसंबर, 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण का चौथा भाग —

चुनाव- एक बड़ा जुआ

चुनाव पद्धति कितनी विचित्र है—इसका अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि यद्यपि 1971 में कांग्रेस को भी ठीक उतने ही वोट मिले थे, जितने 1977 में जनता पार्टी को प्राप्त हुए थे, फिर भी 43.06 प्रतिशत वोट के बल पर 1971 में कांग्रेस को लोकसभा की 350 सीटें मिली थीं, जबकि जनता पार्टी को 298 स्थान ही प्राप्त हुए। 1980 में कांग्रेस (आई) 42.57 प्रतिशत वोटों के बल पर 66.86 प्रतिशत स्थान ले गई, जबकि 1977 में जनता को 43.06 प्रतिशत वोटों के आधार पर केवल 56.80 प्रतिशत स्थान ही 'लोकसभा' में मिले। कम वोटों के आधार पर अधिक सीटें मिलने का दृश्य 1952 से ही दिख रहा है। ब्रिटेन में इस चुनाव पद्धति के आलोचकों ने कहा है कि इसमें चुनाव एक बड़े जुए का रूप धारण कर लेता है।

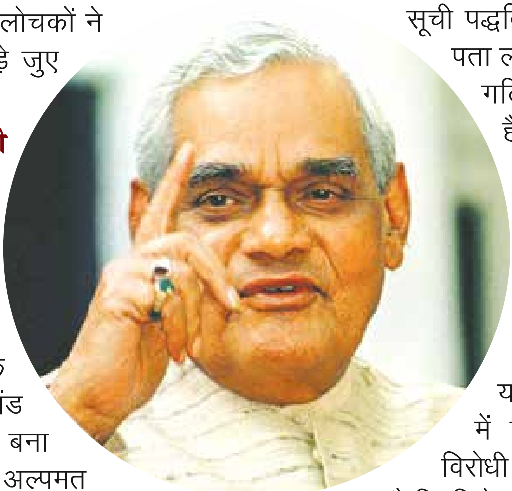

नई चुनाव प्रणाली की आवश्यकता

स्पष्ट है कि वर्तमान चुनाव पद्धति दोषपूर्ण है और वह बहुसंख्या की राय को प्रतिबिंबित नहीं करती। राजनीतिक दल सीटों के बल पर यह गर्वोक्ति करते नहीं थकते कि उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है, किंतु यह तथ्य बना रहता है कि देश के भीतर उन्हें अल्पमत का ही समर्थन है। संसद् या विधानमंडलों में बहुमत के आधार पर महत्त्वपूर्ण फैसले तो कर लिये जाते हैं, कानून भी बनाए जाते हैं, संविधान में भी मूलगामी संशोधन कर दिए जाते हैं, किंतु इनके पीछे बहुमत का समर्थन नहीं होता। यह आवश्यक है कि गत चुनाव परिणामों के प्रकाश में हम चुनाव पद्धति में शीघ्र ही कुछ बुनियादी परिवर्तन करें। वर्तमान बहुमत प्रणाली के स्थान पर हमें सूची पद्धति का अवलंबन करना चाहिए, जो यूरोप के अधिकतर लोकतंत्रवादी देशों में सफलतापूर्वक चल रही है। सूची पद्धति मतदाताओं को जाति और संप्रदाय की संकुचित परिधियों से निकालकर उन्हें दलों की नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ देगी। इससे दलों का बिखराव रुकेगा और दलबदल पर अंकुश लगेगा। चुनाव एक जुआ नहीं रहेगा। संसद तथा विधानमंडलों में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व मोटे तौर पर उन्हें प्राप्त जन समर्थन के अनुरूप होगा। बहुमत प्रणाली के कुछ लाभ अवश्य हैं। एक चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि अपने विकास की ओर अधिक अच्छी तरह से ध्यान दे सकता है। पश्चिम जर्मनी ने दोनों पद्धतियों की अच्छाइयों का समावेश कर एक मिश्रित प्रणाली का विकास किया है। अच्छा होगा कि हम लोकसभा के लिए सूची पद्धति तथा विधानसभाओं के लिए संयुक्त पद्धति का अवलंबन करें।

चुनाव कानूनों में संशोधन के लिए निर्मित संयुक्त संसदीय समिति ने 1973 में यह सिफारिश की थी कि देश में सूची पद्धति लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। यह खेद का विषय है कि उस सिफारिश पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। इस मामले में जनता सरकार का दामन भी बेदाग नहीं है। किंतु हां, उसने कुछ अन्य दूरगामी सुधारों को स्वीकार किया था, जैसे चुनाव का व्यय भार सरकार वहन करे। यह निश्चय हुआ था कि इस संबंध में कानून बनाने से पहले सरकार विरोधी दलों से परामर्श करेगी। मेरी मांग है कि विशेषज्ञ समिति के गठन में अब और देर न की जाए तथा जनता पार्टी सरकार के शासन में स्वीकृत सुझावों को अमल में लाया जाए।

धन-बल के प्रभाव को रोकने की आवश्यकता

चुनाव में पूंजी का बढ़ता हुआ प्रभाव सदैव ही चिंता का विषय रहा है, किंतु अब तो समस्या ने बड़ा खतरनाक रूप ले लिया है। स्वदेशी धन के साथ विदेशी धन के उपयोग के समाचार भी मिले हैं। चुनाव में धन शक्ति के घातक प्रभाव को रोकने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर **गंभीरता से विचार होना चाहिए-**

1. चुनाव का सारा व्यय भार राज्य को वहन करना चाहिए। राजनीतिक दलों को उनके द्वारा प्राप्त मतों के

प्रतिशत के आधार पर अनुदान दिए जाएं। जो उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में सफल हों, उन्हें कानून द्वारा निर्धारित खर्च की सीमा तक वित्तीय सहायता दी जाए।

2. उम्मीदवार के चुनाव व्यय में उसकी पार्टी द्वारा किए गए खर्च को भी जोड़ा जाए।
3. राजनीतिक दलों के चुनाव व्यय की सीमा निर्धारित की जाए।
4. समाचार–पत्रों में विज्ञापनों, पोस्टरों, पर्चों आदि की अधिकतम व्यवस्था की जाए।
5. राजनीतिक दलों के आय–व्यय पत्रकों के ऑडिट की कानूनी व्यवस्था की जाए।
6. तारकुंडे समिति ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने तथा मताधिकार की न्यूनतम उम्र की सीमा घटाकर 18 वर्ष करने के महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिन्हें स्वीकार किया जाए।

जनता सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए रेडियो तथा टेलीविजन का उपयोग करने की सुविधा देकर एक ऐतिहासिक कार्य किया था। इस सुविधा का विस्तार होना चाहिए। चुनाव प्रसारण के अतिरिक्त राजनीतिक प्रसारणों की एक योजना बननी चाहिए।

अनिवार्य मताधिकार का प्रयोग

मताधिकार के उपयोग को अनिवार्य करना भी जरूरी है। देश में अब तक 7 आम चुनाव हो चुके हैं। किंतु ऐसे मतदाताओं की संख्या काफी है, जो चुनाव के प्रति सर्वथा उदासीन हैं और जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। 1977 की तरह 1980 का चुनाव भी अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर लड़ा गया था, फिर भी 35 करोड़ 40 लाख 28 हजार मतदाताओं में से केवल 20 करोड़ 12 लाख 69 हजार ने मताधिकार का उपयोग किया। इसका अर्थ यह है कि 15 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट डालने की आवश्यकता ही नहीं समझी अनेक लोकतंत्रवादी देशों में मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य है।

विदेश नीति

वर्तमान सरकार ने नीति को दलगत राजनीति का खिलौना बनाकर इस मामले में गत तीन दशकों में विकसित राष्ट्रीय सहमति को गहरी क्षति पहुंचाई है। 1977 में जनता पार्टी ने चुनाव का मुख्य मुद्दा घरेलू मामलों को बनाया था। चुनाव जीतने के बाद विदेशी नीति की निरंतरता पर बल दिया था। 1980 और में कांग्रेस (आई) ने विदेश नीति को न केवल चुनाव के अखाड़े में घसीटा, बल्कि उसे अपने चुनाव अभियान का एक प्रमुख मुद्दा भी बनाया। यदि आज पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश के संबंधों में कुछ ठिठुरन दिखाई देती है तो उसका आरंभ चुनाव के दौरान दिए गए इन भाषणों में खोजा जाना चाहिए कि 'हमारे छोटे–छोटे पड़ोसी देश हमें आंखें दिखा रहे हैं।'

पड़ोसी देशों से बिगड़े संबंध

30 वर्षों में पहली बार अच्छे पड़ोसीपन तथा लाभदायक द्विपक्षवाद की नीति का अवलंबन कर जनता सरकार ने इस क्षेत्र में विश्वास का वातावरण बनाने में सफलता पाई थी। पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार करने के पुराने तौर–तरीकों को वापस लाकर इस वातावरण को 12 मास के भीतर ही बिगाड़ दिया गया।

यह आरोप सर्वथा निराधार तथा विद्वेषपूर्ण है कि जनता सरकार ने पड़ोसी देशों की वाहवाही लूटने के लिए राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण हितों की बलि चढ़ा दी। पाकिस्तान के साथ सलाल का समझौता उन्हीं शर्तों पर किया, जिनपर पुरानी सरकार समझौता करना चाहती थी, किंतु करने में विफल रही थी। जहां तक गंगाजल के बंटवारे का सवाल है, 1975 में सरकार ने बांग्लादेश के साथ जो समझौता किया था, उसमें हमारे देश को केवल 11 हजार से 16 हजार क्यूसेक तक पानी मिला था। जनता सरकार पानी की मात्रा को बढ़ाकर 20 हजार 500 क्यूसेक तक ले जाने में सफल हुई।

अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप: ढुलमुल नीति

अफगानिस्तान में सोवियत संघ के सैनिक हस्तक्षेप, जो अब लगभग कब्जे का रूप धारण कर चुका है, के प्रश्न पर भारत सरकार की ढुलमुल नीति ने विश्व में देश की छवि को धूमिल किया है। इसे पड़ोसी देशों, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों और इसलामी मुल्कों से अलग–थलग कर दिया है। सोवियत सैनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध अपनी आवाज असंदिग्ध रूप से उठाने में असफल रहने के लिए हमारे परंपरागत मित्र तथा स्वतंत्रताप्रिय अफगान हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे।

संदिग्ध कंपूचिया नीति

कंपूचिया में वियतनामी सेना के बल पर टिकी सरकार को मान्यता देने का भारत सरकार का फैसला भी किसी सिद्धांत से विहीन और भारत की विदेशी नीति की स्वतंत्रता के बारे में दुनिया में, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, संदेह जगानेवाला है।

यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जनता सरकार ने चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को प्रामाणिकता से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए भी वियतनाम पर चीन के हमले की निंदा करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं की थी। आक्रमण, आक्रमण है; वह चाहे कंपूचिया पर हो या वियतनाम पर भारत आक्रमण को नापने के दो पैमाने नहीं अपना सकता।

मोर्चा सम्मेलन
साल
अमन सोनकर

मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में
9 साल
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण
पूर्ण होने के उपलक्ष्य में
लोकसभा कलस्टर बैठक
मुख्य अतिथि
धर्मपाल जी
BJP

कार्यकर्ता संवाद
साल

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91, शीर्षक कोडः UPHIN16701, डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2022-23
जून प्रथम 2023 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 11–13 (प्रथम पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।